लखनऊ

बुधवार, 2 सितंबर, 2026

वर्ष : 12 । अंक: 9

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

जीवन का सबसे बड़ा गुरु आपका अनुभव होता है, जो हर कदम पर कुछ नया सिखाता है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

भारत वैश्विक बदलावों के बीच भी अपनी ग्रोथ बनाए रखने में सक्षम : वित्त मंत्री सीतारमण

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी ग्रोथ की रफ्तार को कम किए बिना ग्लोबल इकॉनमी में हो रहे बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। उन्होंने देश की आयातित ऊर्जा और फर्टिलाइजर पर निर्भरता को भी स्वीकार किया। जी20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान आईएएनएस को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने भारत को चुनौतियों से निपटने में सक्षम अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। भारत कुछ घरेलू उत्पादन क्षमता होने के बावजूद कई उर्वरकों और उनके कच्चे माल का भी आयात करता है। वित्त मंत्री ने कहा, हम कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े आयातकों में से एक हैं। हम विभिन्न प्रकार के उर्वरकों (यूरिया, अमोनिया, डीएपी) के बड़े आयातक हैं। देश के भीतर उत्पादन क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद हम आयातक हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के आर्थिक प्रदर्शन ने यह दिखाया है कि वह विदेशों में होने वाले घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने और अपनी ग्रोथ की गति को बचाए रखने में सक्षम है। उन्होंने कहा, ये सभी एक जीवंत अर्थव्यवस्था के बहुत स्पष्ट संकेत हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वैश्विक स्तर पर बदलावों को स्वीकार करती है और खुद को इस तरह से ढालती है कि हमारी ग्रोथ प्रभावित न हो। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी समय-समय पर अर्थव्यवस्था का अपना आकलन जारी करता है, जिसमें संकेतक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हां, चुनौतियां हैं, और हम सरकार के तौर पर हर बार चुनौती आने पर भारत को फायदेमंद स्थिति में लाने के लिए काम करेंगे। भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कोलकाता और मुंबई के लाखों लोग हो सकते हैं प्रभावित : यूएन

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कोलकाता और मुंबई में रह रहे लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। जारी रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ने के असर को लेकर कई गंभीर चेतावनियां दी गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर और बर्फ की परतें पिघलती हैं और पानी गर्म होता है, जिससे संपत्ति, लोगों और यहां तक कि संस्कृतियों पर भी असर पड़ता है। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम लीडर्स की 55वीं बैठक में सेक्रेटरी-जनरल अमीना मोहम्मद ने जो रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक 2024 में समुद्र के जलस्तर में सालाना बढ़ोतरी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और यह लगभग छह मिलीमीटर दर्ज की गई है। इस बैठक की मेजबानी पलाऊ कर रहा है, जो प्रशांत महासागर के द्वीपों का एक देश है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से इसके कई द्वीप काफी हद तक डूब सकते हैं। यह बैठक इसी गंभीर खतरे को उजागर कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है, दक्षिण एशिया के निचले डेल्टा इलाकों और भारत के कोलकाता और मुंबई व बांग्लादेश के ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन के रूप में दिख रहा है।

'दुनिया संकटों से जूझ रही, 'झूठ की गूंज' के बीच तेज गति से बढ़ रहा भारत'

7.8% जीडीपी ग्रोथ पर पीएम मोदी का संदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 7.8% जीडीपी ग्रोथ पर खुशी जताते हुए कहा कि जब दुनिया युद्ध समेत विभिन्न संकटों से जूझ रही है तब भी भारत तेज गति से बढ़ रहा है। उन्होंने 7.8% ग्रोथ को देश की सामूहिक शक्ति, संकल्प और पुरुषार्थ का परिणाम बताया। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 7.8 प्रतिशत जीडीपी हासिल कर देश खुशियों से भर गया है। देशवासियों के संकल्प शक्ति के लिए बधाई। यह सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया जब युद्ध में डूबी है, पूरा विश्व संकटों से ग्रस्त है, सप्लाई चेन ध्वस्त है, 2020 के कोरोना काल से अबतक कहीं भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। इसके बावजूद भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।

कुछ लोग निराशा फैलाने में लगे हैं

वहीं भारत के अंदर निराशा के गर्त में डूबे हुए कुछ लोग चारों तरफ झूठ की गूंज और निराशा फैलाने में लगे हैं। इन सबसे ऊपर उठकर और इन रुकावटों को पार करते हुए, देश ने 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल की है। हमें इस रफ़्तार को बनाए रखना होगा। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना ज़रूरी है

'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र अपनाने की सलाह

PM ने कहा, 'हमें 'स्वदेशी' और 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र अपनाना चाहिए। हमें सिर्फ़ मौज-मस्ती के लिए विदेश जाने या विदेश में शादियां करने से बचना चाहिए; इसके बजाय, हमें 'भारत में शादियों' के मंत्र पर चलना चाहिए। जब तक बहुत जरूरी न हो हमें सोना खरीदने से भी बचना चाहिए । हम जितना ज़्यादा 'स्वदेशी' और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देंगे, मुझे उतना ही भरोसा है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक, हम अपने युवाओं को 'विकसित भारत'का उपहार देंगे। आज अपनी कड़ी मेहनत से, हम अपनी युवा पीढ़ी के सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे।

इरादे को हकीकत में बदलने के लिए मिलकर आगे बढ़ें

पीएम मोदी ने कहा, 'आइए हम अपनी कोशिशों में कोई कसर न छोड़ें। हमारी पॉलिसी सही हैं, और हमारे इरादे नेक हैं। 1.4 बिलियन भारतीयों की मिली-जुली ताकत देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एकजुट हो रही है। आइए जश्न मनाएं, पक्का इरादा करें, और उस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए मिलकर आगे बढ़ें।'

2047 के विकसित भारत का लक्ष्य दोहराया

पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश अपनी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सौंपेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को आज की मेहनत और संकल्प के जरिए पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने पुरुषार्थ में कोई कमी न रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति सही दिशा में है और नीयत साफ है। पीएम मोदी के मुताबिक, 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। उन्होंने देशवासियों से 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ की खुशी मनाने के साथ आगे के लिए नया संकल्प लेने और उसे पूरा करने की दिशा में मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

पीएम मोदी का देशवासियों को बड़ा संदेश, बोले- विदेश यात्रा और गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचें

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 7.8 प्रतिशत की शानदार आर्थिक विकास दर हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। इंस्टाग्राम पर एक विशेष वीडियो संदेश साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को 140 करोड़ नागरिकों के संकल्प और पुरुषार्थ की जीत बताया। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक संकटों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का जिक्र करते हुए देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और विदेशी निर्भरता घटाने की पुरजोर अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और कोविड काल के बाद की अनिश्चितताओं से जूझ रही है, इसके बावजूद भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के भीतर ही कुछ लोग घोर निराशा के गर्त में डूबे हैं और लगातार झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने में लगे हैं। इन सभी बाधाओं को पार करते हुए भारत ने 7.8त्न की विकास दर का आंकड़ा छूकर अपनी ताकत साबित की है। अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचें और शादियां विदेशों में (डेस्टिनेशन वेडिंग) करने की बजाय देश में ही करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर बहुत जरूरी न हो तो सोना खरीदने से भी परहेज करें, ताकि देश की पूंजी देश के विकास में काम आ सके। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि नीति सही और नीयत साफ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जितना अधिक स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल देंगे, आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक अपनी युवा पीढ़ी को उतना ही समृद्ध और 'विकसित भारत' सौंप सकेंगे। उन्होंने देशवासियों से अपने पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति के दम पर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया।

जीडीपी ग्रोथ पर खड़गे का तंज : सरकार पीआर में व्यस्त

देश में बेरोजगारी और इन्फ्लेशन चरम पर

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जब उन्होंने 7.8 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ रेट की तारीफ़ की। खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह आम नागरिकों की आर्थिक चुनौतियों को छिपाने के लिए पब्लिक रिलेशंस (PR) का सहारा ले रही है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर एक बयान में, खड़गे ने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया को लाइट्स, कैमरा और इनएक्शन बताया। उन्होंने कहा कि जहाँ सरकार मैक्रो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स (अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने के आंकड़े) को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रही है, वहीं आम आदमी अब भी तीन U

से जूझ रहा है — अभूतपूर्व बेरोज़गारी, असहनीय महंगाई और बेलगाम असमानता।

खड़गे ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और दावा किया कि लगभग 40% युवा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। उन्होंने आगे आंकड़े देते हुए कहा कि जुलाई 2026 तक, 15 से 29 साल की उम्र के हर छह भारतीयों में से एक बेरोजगार था। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के पुराने वादे पर भी निशाना साधा और कहा कि यह वादा पूरी तरह से टूट गया है।

खड़गे ने ज़रूरी चीज़ों की कीमतों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने खुदरा महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि चीनी, प्याज, टमाटर, दाल, खाना पकाने का तेल, चावल और दूध जैसी रोज़मर्रा की रसोई की चीज़ों की कीमतें घरों के बजट पर दबाव डाल रही हैं। उन्होंने पेट्रोल, डीज़ल और LPG की कीमतों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि बढ़ते खर्चों की वजह से आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

दिल्ली वालों को बड़ी राहत! अब ₹35/Kg मिलेगा प्याज, सरकार का महंगाई पर वार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों और उसकी उपलब्धता को लेकर चिंता के बीच, सरकार ने ग्राहकों को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार राजधानी में 1,000 मीट्रिक टन प्याज़ की सप्लाई करेगी, जिसे उचित मूल्य वाली दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) के ज़रिए ₹35 प्रति किलो के भाव पर बेचा जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज़ की कीमतों और उपलब्धता पर बारीकी से नज़र रख रही है और राजधानी में प्याज़ की कोई कमी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि लोगों को ज़रूरी खाने-पीने की चीज़ें किफायती दामों पर मिलती रहें। सब्सिडी वाले प्याज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, सरकार दिल्ली के सभी 13 ज़िलों में एक-एक मोबाइल वैन भी तैनात करेगी।

जन्माष्टमी पर वृंदावन में बाहरी गाड़ियों की नो एंट्री, 3 से 5 सितंबर तक डायवर्जन

आर्यावर्त क्रांति

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के विश्व प्रसिद्ध पर्व को लेकर मथुरा-वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का बड़ा प्लान तैयार किया है। 3 सितंबर सुबह 8 बजे से 5 सितंबर सुबह 9 बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं को मंदिरों तक सुगम और सुरक्षित पहुंचाने के लिए पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 35 सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया, CCTV कैमरों और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। प्रमुख चौराहों और तिराहों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सूचना पट्टिकाएं भी लगाई जा रही हैं। जन्माष्टमी के दौरान भूतेश्वर, मसानी, डींग गेट, चौक बाजार, भरतपुर गेट, गोवर्धन चौराहा, मण्डी चौराहा, कृष्णापुरी और होलीगेट सहित कई स्थानों से कृष्ण जन्मभूमि की ओर जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

कई मार्गों पर चार पहिया वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों को भी आवश्यकता के अनुसार रोका जाएगा। वहीं भारी और कॉमर्शियल वाहनों के लिए अलग-अलग रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे, वृंदावन, NH-19, गोकुल और गोवर्धन की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं।

ममता बनर्जी की भतीजी ने की खुदकुशी, घर से लटका हुआ शव बरामद

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी भतीजी वृष्टि मुखर्जी ने आत्महत्या कर ली है। मंगलवार दोपहर को रामपुरहाट में उनके घर पर उनका शव फंदे से लटका मिला। परिवार का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक, वृष्टि पिछले 4-5 साल से डिप्रेशन से परेशान थीं और इलाज चल रहा था। पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में उनका नाम आने के बाद उनकी सरकारी नौकरी (ग्रुप-सी) छिन गई थी। हाल में तलाक के मामले से भी वे तनाव में थीं। वृष्टि, ममता बनर्जी के ममेरे भाई निहार मुखर्जी की बेटी थीं। निहार रामपुरहाट में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं।

परिवार का ननिहाल रामपुरहाट के कुसुम्बा गांव में है। वे एक स्थानीय स्कूल में ग्रुप-सी कर्मचारी थीं। भर्ती घोटाले की जांच में सेंट्रल एजेंसियों को पता चला कि लगभग 90 प्रतिशत OMR शीट में गड़बड़ी थी। जांच में वृष्टि समेत कई उम्मीदवारों का नाम सामने आया, जिन्हें कथित तौर पर फायदा मिला था। इसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई और उनकी नौकरी चली गई। मंगलवार दोपहर को कुसुम्बा गांव में उनके घर की दूसरी मंजिल की बालकनी में कपड़े के सहारे उनका शव लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर रामपुरहाट पुलिस मौके पर पहुंची। शव को उतारकर जांच के लिए रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया।

ड्राफ्ट लिस्ट से 2 करोड़ से अधिक नाम कटे, नासिक में पुरुषों से कहीं अधिक महिला वोटर्स

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग की ओर से कल सोमवार को जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 2 करोड़ से भी अधिक वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। जबकि एसआईआर शुरू होने से पहले राज्य में 9।78 करोड़ वोटर्स हुआ करते थे। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में नासिक और मुंबई उपनगर में लैंगिक अंतर सबसे अधिक पाया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कल सोमवार को SIR-2026 प्रक्रिया के तहत सभी 288 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले महाराष्ट्र में कुल 9,78,54,049 वोटर्स थे।

केंद्र के आश्वासन के बाद सीजेपी ने 5 सितंबर का दिल्ली मार्च टाला

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पार्टी 5 सितंबर को निकाले जाने वाले मार्च के अपने आह्वान को वापस ले रही है। उन्होंने ऐसा केंद्र सरकार के कोर्ट में दिए गए आश्वासन और उसके बाद कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों को ध्यान में रखते हुए किया है। दास ने कोर्ट से कहा कि CJP के सह-संयोजक के तौर पर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के सकारात्मक आश्वासनों और आज उन्हें मिली न्यायिक मान्यता को देखते हुए, और इस कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए, CJP 5 सितंबर को मार्च निकालने का अपना आह्वान वापस लेना उचित समझता है और आज के आदेश के पालन की उम्मीद करता है।

केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं के साथ हुई बैठक में दिए गए तीनों वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला वादा यह था कि केंद्र 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच दर्ज FIR पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरा वादा यह था कि इस मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। तीसरा वादा यह था कि सरकार उन छात्रों के परिवारों को मुआवज़ा देगी, जिन्होंने कथित तौर पर NEET पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली थी। SG तुषार मेहता: 'फिलहाल, हम तीनों वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' SGI मेहता के कोर्ट से केंद्र सरकार और CJP के बीच हुई बातचीत को मंज़ूरी देने का अनुरोध करने के बाद, सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखी।

वोट काउंटिंग के लिए टोटलाइजर मशीन के उपयोग की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'केंद्र सरकार का रूख जानना चाहेंगे'

नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव मे मतगणना के लिए टोटलाइजर मशीन के उपयोग की मांग के मामले को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस 2014 मे दाखिल की गई जनहित याचिका में अलग-अलग EVM के वोटों की वार्ड के हिसाब से गिनती करने के बजाय पूरे संसदीय क्षेत्र के वोटों की गणना एक साथ टोटलाइजर से कराने की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिका पर राय मांगी है। CJI ने कहा है कि हम टोटलाइजर इंट्रोड्यूस करने के नियमों में बदलाव पर केंद्र सरकार का रूख जानना चाहेंगे।

याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इसके (टोटलाइजर मशीन के उपयोग) लिए कानूनी बदलाव की जरूरत है-जो आयोग के दायरे में नहीं है। शुरू में आयोग ने सरकार से गुहार लगाई थी, सरकार ने एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी, वह राजी नहीं हुई। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इसका विरोध किया।

फायदे और नुकसान पर हुई चर्चा

CJI ने कहा कि 'मेरे हिसाब से चुनावों की निष्पक्षता के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? जब वे मैन्युअल रूप से गिनती करते हैं, या मशीन में भी, तो आप देख सकते हैं कि कहां छेड़छाड़ हुई है या नहीं। बदकिस्मती से टोटलाइजर के मामले में यह इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। इससे डेमोक्रेसी को क्या बड़ा फायदा होगा?' याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि 'ये चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने का काम करेगा। यह वोटर्स के फायदे मे होगा। कोई नहीं जान सकता कि मुझे किस बूथ से कितना वोट मिला है। कई देश सिर्फ प्राइवेसी के अधिकार को सुरक्षित रखने, चुनाव के बाद की हिंसा से बचने के लिए टोटलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 2007 में टोटलाइजर का सपोर्ट किया था।'

कैसे काम करता है टोटलाइजर सिस्टम?

याचिकाओं में कहा गया है कि टोटलाइजर सिस्टम से अलग-अलग मतदान केंद्रों पर किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, इसका पता नहीं चलेगा। इससे चुनाव के बाद मतदाताओं को निशाना बनाने, उनके साथ भेदभाव करने और हिंसा की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। टोटलाइजर में कई मतदान केंद्रों के वोटों को एक साथ गिनने का प्रावधान होता है। इससे किसी खास बूथ के वोटिंग पैटर्न का पता नहीं चलता।

इंडिगो फ्लाइट का हवा में इंजन हुआ फेल, 14 हजार फीट पर मचा हड़कंप, पायलट ने कराई सुरक्षित लैंडिंग

पणजी। गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में मंगलवार सुबह हवा में अचानक इंजन फेल होने से हड़कंप मच गया। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान के एक इंजन में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने गोवा एयरपोर्ट पर तुरंत 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी। पायलटों की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित वापस गोवा एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया, जिससे विमान में सवार सभी यात्रियों की जान बाल-बाल बच गई।

जानकारी के अनुसार, इंडिगो की उड़ान 6ई 2102 ने सुबह 9.16 बजे दिल्ली के लिए गोवा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। एविएशन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के डेटा के मुताबिक, जब विमान दक्षिण महाराष्ट्र के तटीय इलाके के ऊपर लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी उसके एक इंजन में खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए एटीसी को आपातकालीन संदेश भेजा। एटीसी ने सुबह करीब 9:30 बजे फुल इमरजेंसी घोषित करते हुए विमान को प्राथमिकता के आधार पर लैंडिंग की अनुमति दी।

पायलटों ने संयम बरतते हुए सुबह 9.51 बजे विमान को गोवा एयरपोर्ट के रनवे 28 पर सुरक्षित उतार लिया। इसके बाद सुबह 10:03 बजे एटीसी ने स्थिति पूरी तरह सामान्य होने पर फुल इमरजेंसी समाप्त की। विमान के बे नंबर 6 पर पार्क होने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें एयरपोर्ट के बोर्डिंग लाउंज में ठहराया गया।

सहारनपुर में पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ के नकली नोट... कहां हुई चूक, एसआईटी करेगी पूरी जांच

सहारनपुर में पीएनबी शाखा की करेंसी चेस्ट में नकली नोट मिलने का मामला गंभीर

» शुरुआती जांच में करीब 7.40 करोड़ रुपये की नकली करेंसी सामने आई थी

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। सहारनपुर के घंटाघर स्थित सोफिया मार्केट की पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शाखा की करेंसी चेस्ट में नकली नोट मिलने का मामला अब बेहद गंभीर रूप ले चुका है। शुरुआती जांच में जहां करीब 7।40 करोड़ रुपये की नकली करेंसी सामने आई थी, वहीं सूत्र बता रहे है कि जांच आगे बढ़ने के साथ यह आंकड़ा बढ़कर करीब 17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

करेंसी की जांच अभी जारी है, इसलिए नकली नोटों की कुल रकम और बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। करोड़ों रुपये की नकली करेंसी का बैंक की करेंसी चेस्ट तक पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल है। मामला सामने आने के बाद बैंक के अधिकारियों से लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तक में हलचल मची हुई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सहारनपुर रेंज के DIG अभिषेक सिंह भी सोफिया मार्केट स्थित पीएनबी की करेंसी चेस्ट पहुंचे। उन्होंने करेंसी चेस्ट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी ली। DIG ने बैंक अधिकारियों से नकदी के रखरखाव, करेंसी की जांच, बंडल तैयार करने की प्रक्रिया और चेस्ट में कैश के आने-जाने से जुड़े रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी हासिल की।

पुलिस अब बैंक की आंतरिक जांच के साथ अपने स्तर पर भी मामले की कड़ियां जोड़ रही है। इससे पहले जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन सिंह

एसआईटी करेगी इन मामले में इन बातों की जांच

SIT की जांच में मुकदमे में नामजद बैंक अधिकारियों और अन्य आरोपियों की भूमिका खंगाली जाएगी। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि करोड़ों रुपये की नकली करेंसी करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंची और इसमें बैंक के अंदर या बाहर कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस की जांच अब सिर्फ नकली नोटों की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि नकली करेंसी के स्रोत और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने पर भी फोकस रहेगा। इस पूरे मामले की परतें उस समय खुलनी शुरू हुईं जब करेंसी चेस्ट से करीब 11।50 करोड़ रुपये की करेंसी आरबीआई की जयपुर चेस्ट भेजी गई। करेंसी को जयपुर भेजने की प्रक्रिया के दौरान बैंक में पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार को नोटों की गड्डियां लगाने का काम दिया गया था।

भी मामले को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP अभिनंदन सिंह ने विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर दी है। अब यह टीम पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करेगी।

पीएनबी के मुख्य प्रबंधक को सहारनपुर भेजा गया

जयपुर पहुंचने के बाद करेंसी की गिनती हुई तो करीब 4 लाख 30 हजार 900 रुपये कम मिले। इसके बाद जयपुर चेस्ट से पीएनबी मेरठ के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। बैंक ने मामले की जांच शुरू कराई। जांच अधिकारी के तौर पर पीएनबी के मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे को सहारनपुर भेजा गया। पड़ताल में हाउस कीपर विशाल कुमार द्वारा नोटों की गड्डियों से रुपये निकालने की बात सामने आई। यह गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में भी कैद बताई गई है। रुपयों की कमी का मामला सामने आने के बाद 9 अगस्त से करेंसी चेस्ट का ऑडिट शुरू कराया गया। इसी दौरान बैंक अधिकारियों को पता चला कि मामला केवल कुछ लाख रुपये की कमी का नहीं है। करेंसी की जांच और मिलान के दौरान करीब 7।40 करोड़ रुपये की नकली करेंसी मिलने की बात सामने आई।

कई अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो नकली नोटों की मात्रा बढ़ती गई और अब यह आंकड़ा करीब 17 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। अभी करेंसी चेस्ट में मौजूद सभी नोटों की जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अंतिम आंकड़ा सामने आने में अभी समय लग सकता है। करेंसी चेस्ट में नकली नोट मिलने के बाद बैंक के कई अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई।

जांच के दौरान वरिष्ठ मंडल प्रबंधक रवि कुमार कांसे, करेंसी चेस्ट प्रबंधक सुशील कुमार और यमुनानगर-जगाधरी स्थित करेंसी चेस्ट के प्रबंधक अमित कुमार के नाम सामने आए। बैंक की ओर से इन अधिकारियों से मामले को लेकर जानकारी मांगी गई। जांच अधिकारी के मुताबिक, नकली करेंसी के संबंध में मिले जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए।

बैंकिंग सिस्टम की निगरानी पर सवाल

अब SIT यह भी जांच करेगी कि हाउस कीपर द्वारा रुपये निकालने की घटना का 17 करोड़ रुपये की नकली करेंसी से कोई संबंध है या दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं। इस मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर करोड़ों रुपये के नकली नोट बैंक की करेंसी चेस्ट तक पहुंचे कैसे? करेंसी चेस्ट में बड़ी मात्रा में नकदी जमा होती है और उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत दूसरी बैंक शाखाओं या आरबीआई चेस्ट तक भेजा जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोटों का यहां तक पहुंचना बैंकिंग सिस्टम की निगरानी और करेंसी सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट किसी दूसरी बैंक शाखा से आए थे या किसी अन्य करेंसी चेस्ट के जरिए यहां पहुंचे। यह भी जांच होगी कि कहीं बैंकिंग चैनल के जरिए जमा हुई नकदी में नकली नोट शामिल तो नहीं थे। जांच का एक अहम बिंदु करेंसी की जांच में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी हैं। यदि करोड़ों रुपये की करेंसी को मशीनों से जांचा गया था तो इतने बड़े पैमाने पर नकली नोटों की पहचान क्यों नहीं हो सकी? अगर मशीनों से जांच नहीं हुई तो प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया?

पुलिस और बैंक की जांच में ये भी देखा जाएगा

पुलिस और बैंक की जांच में यह भी देखा जाएगा कि करेंसी चेस्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें सही तरीके से काम कर रही थीं या नहीं और नकदी सत्यापन की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास थी। SIT के सामने अब करेंसी चेस्ट से जुड़े कई अहम रिकॉर्ड होंगे। इनमें कैश मूवमेंट, नोटों के बंडल, सील, बैंक रजिस्टर, गिनती के दस्तावेज और करेंसी चेस्ट में रकम आने-जाने का पूरा रिकॉर्ड शामिल है।

जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि संबंधित रकम किस तारीख को चेस्ट में पहुंची, किस शाखा या चेस्ट से आई, किसने गिनती की, किस मशीन से सत्यापन हुआ और उसे किस अधिकारी ने स्वीकार किया। यदि नकली नोट किसी दूसरे करेंसी चेस्ट या बैंकिंग चैनल से आए हैं तो जांच वहां तक भी पहुंच सकती है। मामले में नकली करेंसी की रकम करीब 17 करोड़ रुपये तक पहुंचने के बाद जांच का दायरा और बड़ा होने की संभावना है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए CBI जांच की संभावना की चर्चा भी तेज हो गई है।

3 अधिकारियों ने दर्ज कराया केस

इसके बाद बैंक के उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी गई। 29 अगस्त की शाम तीनों अधिकारियों के खिलाफ थाना सदर बाजार में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। बैंक की ओर से तीनों अधिकारियों को निलंबित किए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि उनकी वास्तविक भूमिका क्या रही और नकली करेंसी बैंक की करेंसी चेस्ट तक किस रास्ते से पहुंची, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही होगा। करेंसी की गिनती के दौरान रकम कम मिलने के मामले में पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार की भूमिका सामने आई। बैंक की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस पर नोटों की गड्डियों से रुपये निकालने का आरोप है। इसके बाद उसके खिलाफ रुपये चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया और उसे काम से हटा दिया गया।

पुलिस और बैंक अपने-अपने स्तर पर कर रहे जांच

हालांकि फिलहाल पुलिस और बैंक अपने-अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। आगे जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका तय हो सकती है।फिलहाल सहारनपुर पुलिस की SIT के सामने सबसे बड़ी चुनौती नकली नोटों के स्रोत तक पहुंचना है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और उनके आपसी संपर्क, बैंक रिकॉर्ड, कैश मूवमेंट और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को जांचा जाएगा।

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि 17 करोड़ रुपये की नकली करेंसी एक साथ बैंक की करेंसी चेस्ट तक पहुंची या लंबे समय से धीरे-धीरे यहां जमा होती रही। जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि इस पूरे मामले में सिर्फ बैंक स्तर की लापरवाही हुई या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि करेंसी चेस्ट में पहुंची करोड़ों की नकली करेंसी आखिर आई कहां से और बैंकिंग सिस्टम की कई परतों को पार कर यहां तक पहुंचने के बावजूद पकड़ में क्यों नहीं आई?

चोक नालियां, बजबजाता कचरा और गड्ढों में तब्दील सड़क खोल रही विकास की पोल

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। वि.खं. बल्दीराय अंतर्गत ग्रामसभा तिरहुति बाजार के सिसोदिया नगर (ईश्वरी सिंह का पुरवा) में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सत्य नरायन सिंह (मल्हू) व जुगराज सिंह के घर से अशोक सिंह के घर तक करीब 200 मीटर सड़क गड्ढों, कीचड़ और जलभराव की समस्या से जूझ रही है। सड़क के नीचे बनी नालियां भी चोक पड़ी हैं, जिससे गंदा पानी रास्ते पर फैल रहा है।

दस साल में न मरम्मत, न व्यवस्था, कहां गया विकास का पैसा ?

ग्रामीणों के अनुसार उक्त सड़क का निर्माण करीब दस वर्ष पूर्व हुआ था। आरोप है कि निर्माण के बाद से अब तक सड़क की समुचित मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की दिशा में प्रभावी कार्य नहीं कराया गया। सवाल यह है कि यदि सड़क लगातार जर्जर होती रही तो नियमित अनुरक्षण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार व्यवस्था ने आखिर क्या कदम उठाए ? ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए सरकारी धन खर्च होने के बावजूद धरातल पर उसका अपेक्षित लाभ दिखाई नहीं दे रहा है।

चोक नाली बनी बीमारी का खतरा

नालियों में जमा कचरा और गंदा पानी मच्छरों तथा दुर्गंध का कारण बना हुआ है। बरसात के दिनों में समस्या और विकराल हो जाती है। ग्रामीणों को आशंका है कि लंबे समय तक जलभराव और गंदगी बनी रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके बावजूद सफाई और जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था न होना जिम्मेदार तंत्र की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

जीरो टॉलरेंस के दावों की जमीनी परीक्षा

प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी विकास व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन सिसोदिया नगर की तस्वीर इन दावों की जमीनी परीक्षा ले रही है। यदि सड़क और नाली के निर्माण, मरम्मत अथवा सफाई के नाम पर कभी सरकारी धन खर्च हुआ है, तो उसकी कार्ययोजना, स्वीकृति, भुगतान, माप पुस्तिका और मौके पर हुए कार्य की जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

ग्रामीणों ने उठाई जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग से सड़क और नाली की तत्काल जांच कराकर समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग उठी है कि पूर्व में कराए गए विकास कार्यों और उन पर खर्च सरकारी धन का स्थलीय सत्यापन कराया जाए। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों की समस्या का संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं या विकास के कागजी दावों के बीच यह पुरवा बदहाली का दंश झेलता रहेगा।

तीसरी बार कुलदीप गुप्ता बने काउंसिल ऑफ उद्योग व्यापार मंच के जिलाध्यक्ष

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। नीति आयोग एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा पंजीकृत संस्था काउंसिल ऑफ उद्योग व्यापार मंच, सुल्तानपुर की जिला कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत कोर कमेटी की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव सिंह, चुनाव प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता रमेश माहेश्वरी तथा मंडल अध्यक्ष अशोक कसौधन की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में कोर कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से कुलदीप गुप्ता को लगातार तीसरी बार जिलाध्यक्ष चुना। वहीं राजेश महेश्वरी को जिला महामंत्री तथा रवि सोनी को नगर अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। उपस्थित पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव सिंह ने कहा कि हमें विश्वास है कि नई टीम

पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता एवं चुनाव प्रभारी रमेश माहेश्वरी ने कहा कि सर्वसम्मति से हुआ यह चयन संगठन की एकता और मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक है।

नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कुलदीप गुप्ता ने सभी पदाधिकारियों एवं कोर कमेटी के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी ने जिस विश्वास के साथ मुझे पुनः यह जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर शत-प्रतिशत खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर बृजेश खत्री, राजेंद्र जायसवाल, अरविंद द्विवेदी, विजय टंडन, संतोष जायसवाल, अशोक दिव्या, राजीव श्रीवास्तव, सुधीर गुप्ता, अश्वनी वर्मा, हरिशंकर, मनोज जैन, माणिकलाल, शुभम जैन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पेपर विवाद, मारपीट और छात्रा की मौत... हरदोई के स्कूल में क्षमा के साथ क्या हुआ उस दिन?

आर्यावर्त संवाददाता

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कक्षा आठ की 13 साल की छात्रा की इलाज के दौरान मौत के बाद मामला गंभीर हो गया है। पचदेवरा थाना क्षेत्र के सहुआपुर गांव की रहने वाली क्षमा दीक्षित के परिजनों ने स्कूल में मारपीट के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया है। मामले में शिक्षा विभाग और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी इंचार्ज प्रधानाध्यापक और टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है।

घरवालों के मुताबिक, 20 अगस्त को परीक्षा के दौरान पेपर देखने को लेकर क्षमा का एक सहपाठी छात्रा से विवाद हो गया था। आरोप है कि कहासुनी के बाद सहपाठी ने क्षमा के साथ मारपीट की। इसके बाद वह शिकायत लेकर शिक्षक के पास पहुंची। परिवार का आरोप है कि शिक्षक ने उसकी बात सुनने के बजाय उसके साथ भी

मारपीट की और दोनों हाथ मरोड़ दिए। हाथों में फ्रैक्चर हो गया।

परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद से ही क्षमा की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। स्कूल पहुंचे स्वजन को शिक्षक की ओर से इलाज कराने की बात कही गई थी। करीब दो दिन इलाज के बाद भी हालत में सुधार नहीं होने पर 23 अगस्त को उसे फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हालत बिगड़ी तो निजी अस्पताल में कराया भर्ती

लोहिया अस्पताल में हालत गंभीर होने पर परिजन क्षमा को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान रविवार रात उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान दिए गए कथित अंतिम बयान ने परिवार और आसपास के लोगों को झकझोर दिया। परिजनों के अनुसार, कराहती हुई क्षमा के मुंह से निकला- मेरी कोई नहीं मानता। हालांकि, इस कथित अंतिम बयान और छात्रा की मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होनी बाकी है।

बेटी की मौत के बाद पिता ने पुलिस से लगाई गुहार

बेटी की मौत के बाद पिता उमेश दीक्षित ने पुलिस को तहरीर देकर स्कूल के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल में हुई घटना के बाद ही बेटी की हालत बिगड़ी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। सोमवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। मां संगीता देवी समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी भरखनी सुनील कुमार के अनुसार, आरोपी इंचार्ज प्रधानाध्यापक राजेंद्र गंगवार और कक्षाध्यापक अच्छे सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया है। एएसपी सुबोध गौतम ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

पुलिस छात्रा की मौत के मामले में शिक्षक और सहपाठी छात्रा की भूमिका समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष से ही स्पष्ट होगा कि छात्रा की मौत की वजह क्या थी और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होती है।

मेरी कोई नहीं मानता ने खड़े किए कई सवाल

क्षमा की कथित आखिरी बात ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान होना चाहिए, जहां उनकी बात सुनी जाए और शिकायत पर उन्हें संरक्षण मिले। यदि जांच में शिक्षक पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो मामला महज अनुशासन का नहीं, बल्कि एक बच्चे की शिकायत को कथित तौर पर गंभीरता से न लेने का भी होगा। 13 साल की बच्ची के आखिरी शब्द अब जांच के साथ-साथ इस सवाल को भी सामने ला रहे हैं कि जब वह मदद मांग रही थी, तब उसकी आवाज कितनी गंभीरता से सुनी गई।

यूपी में महंगी हुई जमीन, बरेली में 50% तक तो मुरादाबाद में 12% तक बढ़े दाम

बरेली में जमीन के सर्किल रेट 50% तक बढ़े » नोएडा में जमीन के अलॉटमेंट रेट 11% बढ़े » मुरादाबाद में औसतन 12% महंगी हुई जमीन

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदना अब और महंगा होने जा रहा है। बरेली में नए सर्किल रेट लागू होने के बाद कई इलाकों में जमीन के दाम 50% तक बढ़ गए हैं, जबकि मुरादाबाद में औसतन 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नोएडा में अथॉरिटी की जमीन की अलॉटमेंट रेट पहले ही 11% तक बढ़ चुकी हैं। लखनऊ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी जमीन के रेट बढ़ने की तैयारी है। ऐसे में आने वाले समय में प्लॉट, मकान और जमीन की रजिस्ट्री पर लोगों को पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आइए आपको बडे.शहरों में दाम कितने बढ़े हैं और आगे बढ़ने की संभावना कितनी है उसके बारे में बताते हैं।

बरेली में जमीन और प्रॉपर्टी के नए सर्किल रेट मंगलवार यानी 1 सितंबर 2026 से लागू हो गए हैं।

इलाके की अहमियत, जमीन के इस्तेमाल, मार्केट रेट और बढ़ती रिहायशी-कमर्शियल एक्टिविटी को देखते हुए ज्यादातर जगहों पर 5 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुछ इलाकों में रेट 50% तक बढ़े हैं। इसका सीधा असर जमीन, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर पड़ेगा। पीलीभीत बाइपास, डोहरा रोड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चुने गए गांवों में खेती की जमीन के रेट सबसे ज्यादा बढ़े हैं। डोहरा और नवादा जोगियान में सर्किल रेट 33 हजार से बढ़कर 39 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर हो गया है। वहीं, इटौआ बेनीराम, लालपुर और चंदपुर बिचपुरी में यह रेट 26 हजार से बढ़कर 39 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर हो गया है। नई दरें लागू करने से पहले 193 आपत्तियों का निपटारा किया गया।

मुरादाबाद में औसतन 12% महंगी हुई जमीन

मुरादाबाद में भी नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं। जिले में औसतन 12% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, हाईवे के किनारे खेती की जमीन खरीदने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब 600 मीटर से ज्यादा दूरी पर जमीन खरीदने की स्थिति में अकृषक रेट के बजाय कृषक रेट पर रजिस्ट्री कराई जा सकेगी, जिसमें 50% की अतिरिक्त बढ़ोतरी लागू होगी। खास बात यह है कि लगातार दूसरे साल कमर्शियल और कंस्ट्रक्शन रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपत्तियों के निपटारे के बाद नई रेट लिस्ट को फाइनल मंजूरी दी गई है।

नोएडा में 11% तक बढ़ चुके हैं जमीन के रेट

नोएडा में मई 2026 से जमीन खरीदना महंगा हो चुका है। नोएडा अथॉरिटी ने अलग-अलग कैटेगरी में जमीन की अलॉटमेंट रेट में अधिकतम 11% तक बढ़ोतरी की है। रिहायशी जमीन में ए कैटेगरी की दर 1,32,860 रुपये से बढ़कर 1,47,480 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है। इसी तरह बी कैटेगरी में रेट 92,620 से बढ़कर 1,02,810 रुपये, सी में 67,440 से 74,860 रुपये, डी में 56,370 से 62,570 रुपये और ई कैटेगरी में 51 हजार से बढ़कर 56,610 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गया है। ग्रुप हाउसिंग और इंडस्ट्रियल जमीन की अलॉटमेंट रेट में भी 11% तक की बढ़ोतरी हुई है।

गाजियाबाद में 50 गज का प्लॉट कितने का?

गाजियाबाद में बढ़ती डिमांड और जमीन से जुड़े खर्च बढ़ने के कारण छोटे प्लॉट भी महंगे हो गए हैं। 99acres के डेटा के मुताबिक, अलग-अलग इलाकों में 50 गज यानी करीब 45 वर्गमीटर के प्लॉट की कीमत लगभग 35 लाख से 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा तक पहुंच रही है। वहीं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कुछ योजनाओं में 40 वर्गमीटर के छोटे प्लॉट की शुरुआती कीमत करीब 14 लाख रुपये है। शहर में पिछले दो साल से सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन 2026 के लिए नए रेट का सर्वे चल रहा है। ऐसे में आगे जमीन की सरकारी दरों में बदलाव हो सकता है।

लखनऊ में 17% तक बढ़ सकते हैं सर्किल रेट

राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित सर्किल रेट में करीब 17% तक बढ़ोतरी की बात सामने आई है। मैजिकब्रिक्स के डेटा के मुताबिक, बाहरी इलाकों में रेट करीब 14 हजार से बढ़कर 16,400 रुपये प्रति वर्गमीटर हो सकता है। सुल्तानपुर रोड-शहीद पथ पर यह रेट 25 हजार से बढ़कर करीब 29,300 रुपये और सीतापुर रोड पर 39 हजार से करीब 45,700 रुपये प्रति वर्गमीटर हो सकता है। गोमती नगर के प्रमुख इलाकों में रेट करीब 40 हजार से बढ़कर 46,800 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं, हजरतगंज-कालीदास मार्ग जैसे महंगे इलाके में यह 76 हजार से बढ़कर करीब 89 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर हो सकता है।

ग्रेटर नोएडा में 25% तक बढ़ सकते हैं रेट

ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट करीब 25% तक बढ़ने की संभावना है। इसका सबसे ज्यादा असर जेवर एयरपोर्ट के आसपास की खेती की जमीन पर पड़ सकता है। यहां जमीन के सर्किल रेट में करीब 70% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। एयरपोर्ट और उससे जुड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की वजह से इस इलाके में जमीन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। वहीं, नोएडा के सेक्टर 14A, 15A और 44 जैसे प्रीमियम इलाकों में भी रेट बढ़ने की संभावना है। मौजूदा 1.03 लाख से 1.12 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर की दर बढ़कर करीब 1.2 लाख से 1.4 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

पूरे यूपी में कितना और बढ़ सकता है जमीन का भाव?

उत्तर प्रदेश में करीब नौ साल बाद सर्किल रेट में बड़े बदलाव की तैयारी है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2026 से नए सर्किल रेट लागू करने की प्रोसेस शुरू की थी, लेकिन इसे कई बार टाला गया और अगस्त तक मामला रिव्यू में रहा। प्रस्तावित बदलाव में अलग-अलग इलाकों और जमीन की कैटेगरी के हिसाब से 20 से 70% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इसका असर खास तौर पर हाई-राइज अपार्टमेंट, खेती की जमीन और तेजी से डेवलप हो रहे इलाकों पर पड़ सकता है। हाई-राइज अपार्टमेंट के रेट में करीब 20% तक बढ़ोतरी की संभावना है।

राजधानी हुई पानी-पानी, लगातार होती रही झमाझम बारिश, सड़क पर कमर तक जलभराव, घंटों जाम में फंसे वाहन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी में मंगलवार दोपहर करीब दो घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। आसमान में काले बादल छा गए और दिन में ही अंधेरा जैसा नजारा हो गया। तेज बिजली कड़कने के बीच वाहन चालकों को हेडलाइट और डिपर जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ीं। लगातार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई।

शहीद पथ, कमता तिराहा, पॉलीटेक्निक और बुद्धेश्वर चौराहा समेत कई प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। गोमतीनगर और इंदिरानगर में करीब दो फीट तक पानी भरने की सूचना है। कई घरों में भी पानी घुस गया और लोगों

को परेशानी का सामना करना पड़ा। चिनहट समेत कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

चिनहट में धंसी करीब 8 फीट सड़क

चिनहट के रोलेक्स अपार्टमेंट के सामने सीवर मैनहोल के पास करीब आठ फीट सड़क धंस गई। सड़क धंसने से मौके पर खतरा बढ़ गया और आवागमन प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक लगातार बारिश और जलभराव के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। सीतापुर रोड योजना के सब्जी मंडी क्षेत्र में भी तेज बारिश के बाद गलियां पानी से लबालब हो गईं। जलभराव इतना बढ़ गया कि कई घरों में पानी घुस गया। लोगों को घरों से पानी निकालने में मशक्कत करनी पड़ी।

अलग-अलग इलाकों में होती रही बारिश

राजधानी में मंगलवार सुबह से ही अलग-अलग इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह करीब सात बजे मलिहाबाद की तरफ बारिश हुई। इसके बाद करीब 10 बजे जानकीपुरम विस्तार और 11 बजे हजरतगंज में तेज बारिश शुरू हुई। दोपहर करीब ढाई बजे गोमतीनगर, चिनहट और मोहनलालगंज में भी तेज बारिश होने लगी। आंकड़ों के मुताबिक, एक सितंबर तक लखनऊ में सामान्य बारिश का औसत 523.9 मिलीमीटर है, जबकि अब तक 525.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। यानी सामान्य से 1.6 मिलीमीटर अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से पांच सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी है।

बारिश में भीगते हुए किसानों का प्रदर्शन

तेज बारिश के बीच सदर तहसील में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी मौके पर डटे रहे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

अखिलेश यादव से तैराकी और राइफल शूटिंग के पदक विजेता खिलाड़ियों ने की भेंट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से तैराकी और राइफल शूटिंग प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों ने भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में खेल नीति बनाई जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सहायता के लिए एक विशेष कोष भी बनाया जाएगा, जिससे प्रतिभावान खिलाड़ियों को आर्थिक संसाधनों के अभाव में अपनी तैयारी में कठिनाई न हो।इस अवसर पर तैराकी में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले कृष्ण यादव ने अखिलेश यादव से भेंट की। कृष्ण यादव ने थाईलैंड में आयोजित तैराकी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक हासिल किया है। इसके अलावा भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है।गुजरात निवासी राम ब्रजेश यादव ने भी अपने परिवार के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनके नाती आदित्य यादव तथा नातिन अनुष्का हरेन्द्र यादव ने राइफल शूटिंग में कई पदक हासिल किए हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी अर्हता प्राप्त की है।राम ब्रजेश यादव के साथ उनकी पत्नी विनीता राम प्रवेश, आलोक यादव और आर्यन यादव भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव ने सभी खिलाड़ियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मंच के शुद्धिकरण के दोषियों पर एफआईआर और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा निरस्त करने की मांग

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन एवं सांसद तनुज पुनिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के मंच के कथित शुद्धिकरण के दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की।प्रदर्शन के बाद पुलिस ने तनुज पुनिया सहित प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक हिरासत में लेकर ईको गार्डन पहुंचाया। देर शाम सभी को रिहा कर दिया गया।प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. उमा शंकर पाण्डेय ने बताया कि प्रदर्शन में अनुसूचित जाति विभाग के बड़ी संख्या में कांग्रेस

कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए तनुज पुनिया ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार की मानसिकता दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और दलित समाज से आते हैं। हल्द्वानी में उनकी जनसभा के बाद भाजपा के लोगों द्वारा मंच का शुद्धिकरण किया जाना संविधान विरोधी कृत्य है।तनुज पुनिया ने मांग की कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि इस कथित दलित विरोधी कृत्य के खिलाफ आवाज उठाने पर राहुल गांधी के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर भी तत्काल निरस्त की जानी चाहिए।प्रदर्शन और गिरफ्तारी के दौरान डॉ. शहजाद आलम, ममता चौधरी, मुकेश सिंह चौहान, सुशील कुमार वाल्मीकि, विषम सिंह, सिद्धिश्री, मुरली मनोहर, विनय गौतम, विनीत वर्मा, अमरनाथ पासवान, अखिलेश कनौजिया, अभय गौतम, अजय रावत, पंकज बाबा, श्रीराम वर्मा, पावन कोरी, विद्या गौतम, सीमा गौतम, शैलेन्द्र कुमार, अशोक कसोरूया, राम बदन बौद्ध, स्नेहलता, राम हरक रावत, सोम विकल, ग्रुप कैप्टन दिनेश चन्द्रा, आशीष प्रेमी, विजय कुमार, संयोगिता वर्मा, वीरेन्द्र यादव, अफाक अली, सद्दन, इरफान कुरैशी, सहिस्ता अख्तर, बृजेश आर्य, बृजेश गौतम, श्रुति अवस्थी, सूरज दीक्षित और विश्रुत अवस्थी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

हौसलों की उड़ान-2026' में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, जल्द शुरू होगी आधुनिक कंप्यूटर लैब

लखनऊ, 01 सितम्बर (आरएनएस)। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने मंगलवार को लखनऊ स्थित खुन्नू-खुन्नू जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 'हौसलों की उड़ान-2026' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज की छात्राओं से सीधे संवाद किया और शिक्षा के साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी उत्कृष्ट भागीदारी की सराहना की।समारोह को संबोधित करते हुए असीम अरुण ने कहा कि बेटियों में अपार प्रतिभा और आत्मविश्वास है। पढ़ाई के साथ खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी रुचि यह साबित करती है कि वे हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने छात्राओं के उत्साह और प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि पारंपरिक खेलों एवं सांस्कृतिक आयोजनों के

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को सरकार प्रतिबद्ध : केशव प्रसाद मौर्य

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में इस क्षेत्र की अहम भूमिका होगी।उप मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत उपलब्ध सुविधाओं, अनुदानों और प्रोत्साहनों की जानकारी अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि

उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे किसानों की उपज को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें।इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत गठित एग्रेजल समिति की बैठक हुई। बैठक में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त नवीन निवेश प्रस्तावों का परीक्षण किया गया और प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।समिति ने कुल 12 नवीन आवेदनों पर विचार किया। परीक्षण के बाद 10 प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों की पूर्ति के अधीन स्वीकृति के लिए संस्तुति प्रदान की गई। संस्तुत परियोजनाओं में कैटल फीड, अनाज एवं रिफाइंड मसाले, मूंगफली प्रसंस्करण, फ्रोजन एवं अन्य खाद्य उत्पाद, रेडी-टू-कुक उत्पाद, तेल-आटा-दाल-बेसन निर्माण, दाल मिल तथा फ्रोजन फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण से संबंधित इकाइयां शामिल हैं। कुछ परियोजनाओं में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।एग्रेजल समिति ने परियोजनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इनमें स्थानीय किसानों से कच्चे माल की खरीद, आवश्यक प्लांट मैप, अग्निशमन एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण-पत्र, उत्पादन क्षमता के उपयोग, विद्युत बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना शामिल है।समिति ने एक प्रस्ताव को अभिलेखों के आधार पर पात्रता पूरी नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया। वहीं, एक अन्य प्रस्ताव में प्लांट एवं मशीनरी से संबंधित आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद आगामी एग्रेजल समिति की बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

अधिवर्षता आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हुए नौ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में अधिवर्षता आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले नौ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया और उनके दीर्घ एवं सराहनीय सेवाकाल के लिए बधाई दी।समारोह में मुथा अशोक जैन, पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, डॉ. अखिलेश कुमार निगम, पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग, शहाब रशीद खां, पुलिस उपमहानिरीक्षक यूपी-112, आलोक प्रियदर्शी, अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, सुनीता सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय, कमलेश कुमार दीक्षित, पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, अरविन्द मिश्र, पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, हरि गोवन्द, पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण निदेशालय तथा राम नयन सिंह, सेनानायक 49वीं वाहिनी पीएसी गौतमबुद्धनगर को विदाई दी गई। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विभाग में सेवा करने को अपने जीवन का गौरवपूर्ण अनुभव बताया। उन्होंने सेवाकाल के दौरान के अनुभवों और महत्वपूर्ण संस्मरणों को भी साझा किया।पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि अलग-अलग परिवारों और पृष्ठभूमि से निकलकर पुलिस सेवा को अपना कैरियर चुनने वाले ये अधिकारी सेवा के विभिन्न पड़ावों पर एक-दूसरे से जुड़े और आज एक ही दिन विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों ने 30 से 35 वर्ष अथवा उससे अधिक की दीर्घ सेवा के दौरान राष्ट्र, समाज, आमजन और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया है।

लोक हुंकार' जनसंवाद में संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की रक्षा पर मंथन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों से आए नागरिकों के साथ 'लोक हुंकार' जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को गांधी भवन ऑडिटोरियम, कैसरबाग में किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सांसद राकेश राठौर और विधायक वीरेन्द्र चौधरी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के साथ सीधे संवाद के माध्यम से जनभागीदारी और जनपरिवर्तन को बढ़ावा देना रहा।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि जनसंवाद, जनभागीदारी और जनपरिवर्तन के संकल्प के साथ जनता के अधिकारों, सामाजिक

न्याय, समानता और संविधान की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इस संवाद का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उपस्थित नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की आवाज को मजबूत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना सभी की साझा जिम्मेदारी है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा का संकल्प लेने के लिए कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है।अजय राय ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण पैदा किया गया है। उन्होंने बदायूं के दातागंज थाने में एक युवक की संदिग्ध मृत्यु का उल्लेख करते हुए पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मौतों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह स्वयं वहां जाकर मृतक के परिजनों से मिले और उनकी पीड़ा से अवगत हुए।उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता की पीड़ा में उसके साथ खड़े रहेंगे। राहुल गांधी के संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जहां भी लोगों की पीड़ा दिखाई देगी, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचकर पीड़ितों की आवाज उठाएंगे।

संक्षेप

अपहरण कर हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

लखनऊ। थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में अपहरण कर हत्या की घटना में शामिल एक वांछित अभियुक्त को पुलिस टीमों ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान ओमकार साहू पुत्र माधवराम (उम्र करीब 24 वर्ष) के रूप में हुई है। वह वर्तमान में ग्राम खरगापुर, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में रह रहा था। उसका मूल निवास ग्राम सिमरिया, जनपद बेमेतरा, छत्तीसगढ़ बताया गया है।पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के कब्जे से मृतक की फॉर्च्यूनर कार की एक चाबी, 1,466 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।पुलिस घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

पीईटी-2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 7 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 (पीईटी-2026) के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। आयोग ने इस संबंध में 1 सितंबर को शुद्धि-पत्र जारी किया है।आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा/2026 के अनुसार पीईटी-2026 के लिए विज्ञापन 1 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया गया था। इसके तहत पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी। पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 निर्धारित थी।अब आयोग ने पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 तक विस्तारित कर दी है।

मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु एवं भैंस विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।शासनादेश में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाए। साथ ही धनराशि के उपयोग का पूरा विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।शासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत पशुपालकों को पशुधन से जुड़े जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने और पशुधन बीमा व्यवस्था को मजबूत करने में इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा।

यूपी में 2,606 करोड़ रुपये के निवेश वाली तीन औद्योगिक परियोजनाओं को एलओसी जारी करने का निर्णय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश तथा फॉर्च्यून ग्लोबल-500 और फॉर्च्यून इंडिया-500 कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023' के तहत तीन औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने का निर्णय लिया है। इन परियोजनाओं में कुल 2,606 .04 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश शामिल है।औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मैसर्स एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एलओसी जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिल रहा प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक सुरक्षा कवच

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मानसून और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम के बीच उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में यह योजना किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाली क्षति की स्थिति में बीमित किसानों को बीमा कवच के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर

संचालित की जा रही है।योजना के तहत खरीफ की 10 फसलों और रबी की 8 फसलों को अधिसूचित किया गया है। खरीफ फसलों के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत, जबकि रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत तक सीमित है। वार्षिक नकदी फसलों के लिए यह दर अधिकतम 5 प्रतिशत निर्धारित है। शेष प्रीमियम का वहन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में किया जाता है।उत्तर प्रदेश में योजना के तहत किसानों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30.40 लाख किसान योजना से जुड़े थे। वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 31.18 लाख तथा वर्ष 2025-26 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 39.25 लाख तक पहुंच गई।क्षतिपूर्ति वितरण में भी योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2023-24 में 8.20 लाख किसानों को 429.86 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी। वहीं वर्ष 2025-26 में 5.73 लाख किसानों के खातों में 627.52 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि सीधे भेजी जा चुकी है।उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक कुल 352.91 लाख बीमित कृषकों द्वारा 298.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया। वहीं वर्ष 2017-18 से जून 2026 तक कुल 69.46 लाख किसानों को 5,966.87 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।योजना के तहत फसल क्षति के आकलन और क्षतिपूर्ति प्रक्रिया को अधिक सटीक एवं पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

बीबीएयू में एक माह तक मनाया जाएगा 'राजभाषा हिंदी उत्सव-2026'

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में 1 से 30 सितम्बर 2026 तक 'राजभाषा हिंदी उत्सव-2026' मनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस एक माह लंबे उत्सव के दौरान हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इनमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी सहभागिता करेंगे।उत्सव के अंतर्गत हिंदी माह का उद्घाटन, विभिन्न विभागों में हिंदी प्रतियोगिताएं, श्रुतिलेख एवं सुलेख, टिप्पणी एवं प्रारूपण, हिंदी टंकण, राजभाषा सामान्य ज्ञान तथा स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके अलावा सप्त दिवसीय हिंदी कार्यशाला, पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं 'आनंद मठ' पर एक दिवसीय कार्यक्रम, दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने उत्सव पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी उत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति, ज्ञान-परंपरा और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः अभिव्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की विराट सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है और विविधताओं के बीच संवाद, समन्वय तथा सह-अस्तित्व की भावना को मजबूत करती रही है।कुलपति ने कहा कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन केवल हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दैनिक व्यवहार, कार्यालयीन कार्यप्रणाली, अकादमिक चिंतन, शोध-अनुसंधान और ज्ञान-सृजन में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ना चाहिए।

शरीर फूल गया लेकिन उसमें ताकत नहीं बची

भारतीय जनता पार्टी कभी आंदोलन करने वाली पार्टी थी। जब उसके दो सांसद थे तब उसने देश भर में राममंदिर का आंदोलन खड़ा किया था। यह उसके संगठन की ताकत थी और उसके बड़े नेताओं की वैचारिक व सांगठनिक ईमानदारी थी कि पार्टी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाई। भाजपा के संगठन के लिहाज से कहें तो नब्बे का दशक उसका स्वर्णिम समय था। एक तरफ राममंदिर का आंदोलन चल रहा था और दूसरी ओर जब उसके काउंटर में मंडल का आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें भी भाजपा ने अपने समर्थक समूहों को आंदोलित करके मंडल के खिलाफ भी एक व्यापक नैरेटिव बनाया था। मंदिर आंदोलन और मंडल विरोधी आंदोलन ने भाजपा को इतना ताकतवर बनाया कि नब्बे के दशक में उसने तीन बार सरकार बनाई। पहले 13 दिन की, फिर 13 महीने की और फिर पांच साल की। भाजपा उस समय विचारधारा वाली पार्टी थी। चाल, चेहरे और चरित्र की बात करती थी। भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। लगातार छह साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा का वह चरित्र काफी हद तक बचा हुआ था। उसका जीवंत संगठन था और कई बार सरकार के साथ संगठन का भी टकराव हुआ। भाजपा और संघ के संगठन जैसे भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागण मंच आदि सरकार पर दबाव बनाए रखते थे।

अब पिछले 12 सालों में क्या हुआ? भाजपा, उसके अनुषंगी संगठन और संघ के संगठनों की आंदोलन की क्षमता लगभग समाप्त है। वह किसी भी तरह के आंदोलन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर पा रही है। अब सब कुछ सरकार के भरोसे है। संगठन के लोग आराम से बैठे हैं कि सब सरकार देख लेगी। सरकार कैसे देख लेगी! सरकार के पास एजेंसियां हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आदि एजेंसियां हैं और उससे भी ऊपर न्यायपालिका है। याद करें कैसे 2011 और 2012 में दिल्ली में आंदोलन हुए थे। उस समय तक भाजपा और संघ की आंदोलन को प्रभावित करने की क्षमता थी। तभी चाहे वह आंदोलन अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का हो या बाबा रामदेव का हो या निर्भया कांड के विरोध में हुआ आंदोलन हो, हर आंदोलन के दौरान कांग्रेस और उसकी सरकार परेशान हुई। यह आरोप लगाया कि भाजपा व संघ इन आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। यह बात काफी हद तक सही थी कि सीधे आंदोलनों में शामिल होकर उनका नेतृत्व करने की बजाय भाजपा और संघ ने उस समय के जन आक्रोश को परदे के पीछे से एक दिशा दी और उसका राजनीतिक लाभ लिया। आज भाजपा और संघ या कांग्रेस राज के समय इनके द्वारा तैयार किए गए गुरू और प्रवचनकर्ता, कोई भी आंदोलन खड़ा करने में अक्षम हैं।

उलटे भाजपा और संघ के संगठनों की ताकत इतनी कम हो गई है कि सरकार के खिलाफ होने वाले किसी आंदोलन के समानांतर न तो कोई दूसरा आंदोलन कर पाए और न उसे डिफ्यूज कर पाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों समझ रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं तो बाकी चीज की कोई जरुरत नहीं है। उनको यह भी लग रहा है कि उन्होंने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दी तो अब क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी में कोई दम नहीं दिख रहा है। ऐसा सग रहा है कि पार्टी का शरीर फूल गया लेकिन उसमें ताकत नहीं बची है। सोचें, सरकार में आने के बाद से नरेंद्र मोदी को कितनी बार आंदोलकारियों ने झुकाया! यूपीए सरकार के समय के भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई थी। लेकिन इतना आंदोलन हुआ कि सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। ऐसे ही कृषि कानून मोदी सरकार ने बनाए थे और कहा था कि इससे किसानों की किस्मत बदल जाएगी। एक साल तक आंदोलन करके किसानों तीनों कानून वापस कराए। राष्ट्रीय टीवी पर माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिया। सरकार और भाजपा के नेता कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सरकार के पास नैतिक बल नहीं है और संगठन की शक्ति नहीं है। अगर संगठन और विचारधारा बची रहती तो पेपर लीक होने और परीक्षा में गड़बड़ी होने पर संघ का छात्र संगठन और भाजपा का युवा संगठन भी आंदोलित होता। वह कॉकरोच जनता पार्टी को आंदोलन का स्पेस नहीं लेने देता। लेकिन सारे छात्र व युवा नेता इस अति आत्मविश्वास में बैठे रहे कि सरकार सब संभाल लेगी। माना गया कि पुलिस लाठी चला कर छात्रों को भगा देगी और कुछ नहीं होगा। सोचें, एक समय भाजपा स्वंय बड़े आंदोलन खड़े करती थी या हर लोकप्रिय आंदोलनों के पीछे उसका किसी न किसी रूप में हाथ होता था।

'एक देश, एक चुनाव' की चर्चा तेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के आइडिया को लेकर गंभीर हुए, अभी तक वह गंभीरता नहीं दिखी है

अजीत द्विवेदी

अचानक 'एक देश, एक चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी अचानक सक्रिय हो गए हैं और कहा जाने लगा है कि 2029 में ही पूरे देश के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। मीडिया में इस पर बहसें होने लगी हैं। अचानक आई इस तेजी से दो सवाल उठते हैं। पहला तो यह कि सरकार अभी तक परिसीमन और महिला आरक्षण के प्रयास में लगी है तो फिर 'एक देश, एक चुनाव की चर्चा क्यों शुरू हुई और दूसरा सवाल यह कि अगर महिला आरक्षण कानून को सरकार संशोधित नहीं करा पा रही है तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए लाए गए संविधान के 129वें संशोधन विधेयक को कैसे पास कराएगी? ध्यान रहे जिस तरह नारी शक्ति वंदन कानून में बदलाव के लिए लाए गए 131वें संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरुरत है वैसे ही 129वें संशोधन के लिए भी दो तिहाई बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है।

अगर सरकार 129वें संशोधन को पास नहीं करा पाती है तो 2029 में 'एक देश, एक चुनाव संभव नहीं है। इसके बावजूद अगर भाजपा चाहे तो बहुत से राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करा सकती है। इसके लिए उसे अपने शासन वाले राज्यों की सरकारों से संबंधित राज्य की विधानसभा को समय से पहले भंग कराना होगा। अगर भाजपा ऐसा करती है तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के शासन वाले राज्यों पर भी दबाव बनेगा कि वे इस अभियान में शामिल हों। इसके लिए भाजपा को अगले साल होने वाले चुनावों से ही तैयारी शुरू करानी होगी। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां एक साथ चुनाव के लिए तैयार नहीं होंगी। कांग्रेस के पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार के इस प्रयास को असंवैधानिक बताया है तो जेपीसी में शामिल तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने भी इसका विरोध किया है। दोनों ने समिति के सामने अपनी पार्टी की राय स्पष्ट रूप से रख दी है।

इसलिए केंद्र सरकार और भाजपा के पास यह रास्ता बचता है कि वह अपने शासन वाले राज्यों की विधानसभा समय से पहले भंग कराए और एक साथ चुनाव करा कर एक मिसाल बनाए। वैसे लोकसभा के साथ चार राज्यों के चुनाव स्वतः होते हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनाव लोकसभा के साथ में होते हैं। इनके अलावा तीन अन्य राज्यों के चुनाव उसी साल के अंत में होते हैं। इनमें से दो राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। चुनाव आयोग चाहे तो इन तीनों राज्यों का चुनाव मई में लोकसभा के साथ करा सकता है। इस तरह लोकसभा और सात राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।

अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के आइडिया को लेकर गंभीर हुए, अभी तक वह गंभीरता नहीं दिखी है, तो 2030 और 2031 में जिन भाजपा शासित राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां की विधानसभा भंग करा सकते हैं। 2030 में दो राज्यों दिल्ली और बिहार का चुनाव है, जहां भाजपा की सरकार है। 2031 में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव होंगे। इनमें से तीन राज्यों में भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा चाहे तो तीनों राज्यों में समय से पहले चुनाव करा सकती है। अगर 2030 और 2031 के पांच राज्यों के चुनाव समय से पहले होते हैं तो लोकसभा के साथ 12 राज्यों के चुनाव हो सकते हैं।

अगले साल यानी 2027 में सात राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पंजाब और हिमाचल छोड़ कर बाकी पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात में भाजपा की सरकार है। उसके अगले साल यानी 2028 में पांच बड़े राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। इनके अलावा पूर्वोत्तर के चार राज्यों मेघालय, त्रिपुरा, नगालैंड और मिजोरम के चुनाव भी 2028 में हैं। 2027 के चुनावों को तो 2029 तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या 2028 के चुनावों के 2029 के लिए स्थगित किया जा सकता है? विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने के लिए कानून बनाने की जरुरत होगी, जो संभव नहीं दिख रहा है। दूसरा रास्ता राष्ट्रपति शासन लगाने का है। लेकिन यह काम विपक्षी पार्टियों की सहमति के बगैर संभव नहीं है। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि कम से कम उसके शासन वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो। भाजपा शासित राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा कर चुनाव टालना एक संवैधानिक मामला बनेगा, जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अगर राजनीतिक सहमति बने तो 2028 के नौ चुनाव भी 2029 में कराए जा सकते हैं। इस तरह लोकसभा और कम से कम 21 राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। परंतु यह पूरा हिसाब किताब दूर की कौड़ी लग रहा है। संसद से कानून बनाए बगैर और संविधान के प्रावधानों को बदले बगैर 'एक देश, एक चुनाव मुमकिन नहीं दिख रहा है। अगर सरकार दो तिहाई बहुमत जुटा लेती है या विपक्ष को तैयार कर लेती है तभी कानून पास होगा और तब 2028 के चुनाव टाल कर और 2032 तक के चुनाव पहले करा कर 2029 में एक साथ सारे चुनाव कराए जा सकते हैं। अन्यथा इसे 2034 के लिए छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इस पूरी कवायद का कोई खास अर्थ नहीं है और न इसकी कोई जरुरत है। न तो एक साथ चुनाव कराने से कोई बहुत ज्यादा पैसे की बचत होनी है और न बार बार चुनाव होने से कोई कामकाज प्रभावित होता है। पैसे की बचत और कामकाज प्रभावित होने का तर्क पूरी तरह से बेकार है। उलटे हर साल कहीं न कहीं चुनाव होने से सरकारें जवाबदेह बनती हैं। अमेरिका में हर साल चुनाव होते हैं और इस वजह से सरकारें जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह रहती हैं।

व्यंग्य

बाहर के व्यक्ति को चेयरमैन

टाटा परिवार आम चलन को तोड़ कर बाहर के व्यक्ति को चेयरमैन बनाने की उदारता तो दिखाता है, लेकिन उसे स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देता। यानी वह मालिक होने की पारंपरिक मानसिकता से उबर नहीं पाता।

एन. चंद्रशेखरन के चेयरमैन पद छोड़ने से टाटा ग्रुप में जारी विवाद पर विराम जरूर लग गया है, लेकिन यह प्रकरण इस कंपनी समूह की संचालन प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न छोड़ गया है। चंद्रशेखरन इस सदी में टाटा परिवार के बाहर से आए टाटा संस के दूसरे चेयरमैन थे। ऐसे अन्य चेयरमैन साइरस मिस्त्री को विवादों के कारण उनके पद से हटा दिया गया था। उस घटनाक्रम को चंद्रशेखरन मामले से जोड़ कर देखें, तो प्रश्न उठता है कि क्या टाटा परिवार से बाहर से आए अधिकारियों से यह ग्रुप अलग अपेक्षाएं रखता है? क्या यह मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति भले सबसे ऊंचे पद पर हों, लेकिन वे निर्णय टाटा परिवार के मनमाफिक ही लें? समझा जाता है कि एयर इंडिया के प्रबंधन, टाटा समूह के डिजिटल एवं ई-कॉमर्स उद्यमों से संबंधित नीति, साइबर सुरक्षा उपायों, और जैगुआर/ लैंड रोवर परियोजनाओं के संचालन पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा के साथ चंद्रशेखरन के मतभेद गहराए, जिससे नोएल ने उनकी दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव रोक दिया।

इसके पहले मिस्त्री ने कंपनी की कई परियोजनाओं को लेकर दीर्घकालिक नजरिया अपनाया, जिससे फौरी घाटे को वे नजरअंदाज कर रहे थे। समझा जाता है कि इससे रतन टाटा नाराज हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 2016 में मिस्त्री को उनके पद से हटा दिया गया। लगभग वैसी ही घटना चंद्रशेखरन के साथ दोहराई गई है, हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने नए कार्यकाल के लिए खुद के उपलब्ध ना होने की घोषणा की है। बहरहाल, यह गौरतलब है कि टाटा संस के निदेशक मंडल का बहुमत उन्हें एक और कार्यकाल देने के पक्ष में था, जिसे एक तरह से नोएल टाटा ने वीटो कर दिया। इस बात का परोक्ष उल्लेख चंद्रशेखरन ने अपने त्यागपत्र में भी किया है। तो कुल सूरत यह उभरती है कि टाटा परिवार भारत के आम चलन को तोड़ कर अपने से बाहर के व्यक्ति को चेयरमैन जैसा पद देने की उदारता तो दिखाता है, लेकिन उसे स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देता। यानी वह मालिक होने की पारंपरिक मानसिकता से उबर नहीं पाता। नतीजतन, चेयरमैन के स्वतंत्र निर्णय टकराव का कारण बन जाते हैं।

ब्लॉग

सच्चाई vs भ्रम: मनुस्मृति में नारी को लेकर ऐसा लिखा क्या है? जिस पर होता है बवाल

अभिनय आकाश

गोरख पांडे के इन शब्दों को अगर आज के समाज की असलियत कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सोचिए एक किताब जिसे कुछ लोग धर्म की बुनियाद मानते हैं और वहीं कुछ लोग उसे सरेआम जलाकर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के सबसे असरदार और शायद सबसे विवादित ग्रंथ की मनुस्मृति की। आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है? आप में से बहुत सारे लोगों ने गीता को पढ़ा होगा। रामचरितमानस को पढ़ा होगा, महाभारत को पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने प्राचीन पुस्तकों को जो अलग-अलग पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ा होगा। वेदों को पढ़ा होगा और इनसे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसी ही एक प्राचीन पुस्तक है जिसे हम कहते हैं मनुस्मृति। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मनुस्मृति को अपना निशाना बनाया है। पुणे में छात्रों की गूंज नाम के अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से बात की थी और इस दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति में एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे यह किताब महिलाओं की आजादी के खिलाफ है और इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। ऐसा राहुल गांधी ने कहा। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी बार-बार मनुस्मृति को ही अपना निशाना क्यों बनाते हैं? इस किताब का पूरा नाम मानव धर्म शास्त्र है। तो आज सबसे पहले आपको मनुस्मृति के बारे में बताते हैं।

जब हम भारत में धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो अमूमन शुरुआत में दो प्रकार के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। एक जिनको हम श्रुति ग्रंथ कहते हैं जिनको सुना गया समझा गया। एक उनको स्मृति ग्रंथ जिनको सुनने के बाद याद किया गया और फिर उसे लिखा गया। कई बार इनको उनके डिसाइपल्स द्वारा लिखा गया। तो श्रुति के बाद स्मृतियों का जो महत्व है। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म की अगर बात करें तो प्राचीन में बहुत सारे ग्रंथ जो थे वो इन्हीं विधियों से होकर आगे बढ़े हैं। वेदों की बात करें या अरण्यकों की बात करें। ब्राह्मस्य की बात करें या उन स्मृतियों की बात करें जिनमें से एक मनुस्मृति है। स्मृतियों की बात करें तो कुल लगभग 18 स्मृति है। अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें तो 18 स्मृति है। जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति और बहुत सारी। इनमें से पहली स्मृति मनुस्मृति को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने मनु को ज्ञान दिया। ठीक है? मनु ने यही ज्ञान अपने शिष्य भृगु को दिया और भृगु ने अपने इस ज्ञान को आगे मानवता तक बढ़ाया। शुरुआत में ज्ञान की परंपरा को ऐसे बताया गया है।

इस किताब में 12 अध्याय हैं और लगभग 2694 श्लोक इस किताब में हैं। हिंदुओं की ऐसी मान्यताएं है कि इस पुस्तक को सृष्टि के पहले इंसान ने लिखा था और उन्होंने ही इसके जरिए मानवता को तमाम तरह के कानून दिए। मतलब जो सृष्टि में पहला मनुष्य है उसने इसे लिखा। इसीलिए इसे मनुस्मृति कहा जाता है। यहां मनु का मतलब है पहला मनुष्य। हालांकि कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर के के आसपास लिखी गई है और 200 ईसा पूर्व से 200 ईसवी के बीच इसे लिखा गया है। इस ग्रंथ में मनु ने जीवन दर्शन, प्रशासन, समाज की रचना, नीतियां और कानून के बारे में विस्तार से बताया है। यानी समाज को कैसे चलाना है। राजा से लेकर प्रजा तक सबका धर्म क्या होना चाहिए? आचार विचार क्या होना चाहिए? व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये सारी बातें इस पुस्तक में बताई गई है। यह जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय यह पुस्तक लिखी गई तब तक ना तो बाइबल लिखी गई थी और ना ही कुरान लिखी गई थी। शासन और प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था में इस पुस्तक का इस्तेमाल ना सिर्फ भारत में बल्कि कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हुआ जहां पर हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हिंदू कोड बनाने में इस ग्रंथ का काफी इस्तेमाल किया था। लेकिन आजाद भारत के कानून में हमारे संविधान में इस पुस्तक की कोई जगह नहीं है।

यत्र नार्यस्तु पूजयंते रमंते तत्र देवता। हिंदी में इसका मतलब है जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसे आज की नैतिकता से जज नहीं किया जा सकता। बाइबल दास प्रथा को, स्लेवरी को समर्थन देती है। और कई जानकारों का दावा है कि कुरान में भी कई ऐसी बातें हैं जो महिला विरोधी हैं और इस पर आज भी बहस होती रहती है। यह एक विवाद का विषय है। जबकि ये दोनों ही पुस्तकें मनुस्मृति के कई 100 वर्ष बाद लिखी गई थी। यह किताब दहेज के भी खिलाफ है। और तो और इसमें यह भी कहा गया है कि शूद्रों और महिलाओं को भी धर्म के रास्ते पर चलने का पूरा हक है।

2026 के एक फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक विधवा के गुजारे भत्ते के अधिकार को सही ठहराने के लिए मनुस्मृति का ही हवाला दिया था। ये दिखाता है कि ये महज इतिहास के पन्नों में दबी हुई कोई किताब नहीं है। और ये कोई एक आध बार नहीं हुआ है। 2019 से पहले ही सुप्रीम कोर्ट सात से भी ज्यादा बार अपने फैसलों में मनुस्मृति का जिक्र कर चुका था। अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो वहां तो इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा होता रहा है।

25 दिसंबर, 1927 का दिन था जब डॉ. अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। अंबेडकर ने पहले से घोषणा कर दी थी कि वह इस हिंदू ग्रंथ को जलाएंगे। जो जगह उन्होंने इसके लिए चुनी वो महाड़ नाम का महाराष्ट्र का तटीय इलाका था, जो कोलाबा (अब रायगढ़) जिले में था। अंबेडकर मनुस्मृति को जातिवादी और पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ मानते थे। बकौल उनके, मनुस्मृति ऐसा हिंदू ग्रंथ है, जो जाति उत्पीड़न को संस्थागत बनाता था। निचली जातियों, विशेषकर दलितों और महिलाओं के शोषण और भेदभाव को उचित ठहराता था। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर इसका विरोध किया था उन्हीं ने बाद में हिंदू कोड बिल की बहस में महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक दिलाने के लिए मनुस्मृति के ही कुछ प्रोग्रेसिव श्लोकों का इस्तेमाल किया। डॉ. बी आर आंबेडकर ने यह तर्क दिया था कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात ऋषि मनु जैसे स्मृतिकारों द्वारा कही गई थी। 24 फरवरी 1949 को संविधान सभा की बहस के दौरान उन्होंने कहा थाः इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन दो स्मृतिकारों का मैंने उल्लेख किया है—याज्ञवल्क्य और मनु—वे उन 137 स्मृतिकारों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं जिन्होंने स्मृतियों की रचना करने का प्रयास किया था। इन दोनों ने ही यह व्यवस्था दी है कि पुत्री एक-चौथाई हिस्से की हकदार है। यह अत्यंत खेदजनक है कि किसी न किसी कारणवश कुरीतियों और प्रथाओं ने इस मूल विधान के प्रभाव को नष्ट कर दिया; अन्यथा हमारी अपनी स्मृतियों के आधार पर भी पुत्री एक-चौथाई हिस्सा पाने की पूरी हकदार होती। उन्होंने आगे कानूनों की तुलना में रीति-रिवाजों और प्रथाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रिवी काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा न हुआ होता, तो मनुस्मृति ने वर्षों पहले ही महिलाओं और संपत्ति में उनके उत्तराधिकार के अधिकारों को सशक्त बना दिया होता।

कौशाम्बी में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट

यह धमाका सिर्फ हादसा नहीं, व्यवस्था के भी उड़े चीथड़े, कानून का मातम

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। प्रयागराज-कौशाम्बी की सीमा पर स्थित मनौरी बाजार से सटे गांव में अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं है। तमाम घरों को खंडहर करने के साथ यह विस्फोट प्रशासनिक व्यवस्था के चीथड़े उड़ा गया। यह हादसा उन जिम्मेदारों की धुंधली होती नजर की ओर इशारा कर गया, जिन्हें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन के पास जमा हो रहा विस्फोटक का जखीरा नहीं दिख सका। जिन्हें इस इलाके में गुपचुप हो रहे निर्माण नहीं दिखे, जिन्हें इस रिहायश में जमा हो रहे विस्फोटक नहीं दिखे, उन्हें उन घरों की वेबसी भी शायद ही दिखे जो अपनों को खो चुके हैं। आरोपियों के घरों तक बुलडोजर पहुंच जाएंगे,

उनके कुछ छज्जे व दीवारें गिरेंगी और कड़ी कार्रवाई का स्वांग भी भरपूर दिखेगा। लेकिन, बिजली की हाईटेंशन लाइन के ठीक नीचे मकान बनने देना, उसमें पटाखे बनने देना, शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होना और ऐसे ही मामले में गिरफ्तार हो चुके आरोपी के फिर उसी काम में लग जाने के लिए कौन-कौन से महकमे जिम्मेदार हैं, कौन से अफसर जिम्मेदार हैं, इस पर तो चर्चा तक नहीं शुरू हो सकी है।

व्यवस्था का ये आलम है कि कौशाम्बी जिला बने वर्षों बीत गए, लेकिन उसकी निर्भरता प्रयागराज पर पहले जैसी ही है। तभी तो रुक-रुककर हो रहे धमाकों को रोकने और धधकती राख को शांत करने के लिए प्रयागराज से फायरब्रिगेड आने का इंतजार करना पड़ा। तभी तो सरकारी मदद पहुंचने में देरी के चलते घायलों को बचाने का काम लोगों को खुद करना पड़ा। खटोले पर शव और घायलों को लेकर लोगों के वीडियो सामने आने लगे, उसके बाद एंबुलेंस दिखाई दीं। खंडहर में दबीं सांसों को चलाते रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं दिखा। जिन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है, उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए।

हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। पांच लोग घायल हैं। मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू कराया गया। मलबा हटाकर अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पटाखा फैक्टरी अवैध रूप से संचालित थी। संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। शासनादेश के अनुसार आरोपी की जमीन कुर्क करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

-डॉ. अमित पाल, डीएम, कौशाम्बी

कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट केस में एक्शन, 7 पुलिसवाले सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में 31 अगस्त को अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के दौरान भीषण विस्फोट हो गया था। इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये घटना कौशांबी के पिपरी थाना क्षेत्र के चिल्ला शाहबाजी गांव में अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के कारखाने में हुई थी। अब इस भीषण विस्फोट के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। लापरवाही बरतने पर पिपरी थाना के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर समेत सात पुलिसकर्मियों गाज गिरी है। सातों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर शिवचरण राम, सब इंस्पेक्टर विकास सिंह, सब इंस्पेक्टर विनय सिंह, सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अभिषेक गुप्ता, सब इंस्पेक्टर मनीष पाल और सब इंस्पेक्टर अमित द्विवेदी शामिल हैं।

खौफनाक खुलासा : लाश के 18 टुकड़े, मैदा में पकाए, बैग में भरकर ट्रेन में रखे ; दंपती ने इसलिए की निशा की हत्या

गुड्डुवांचरी के किराए के मकान में तीनों साथ रहने लगे तो विवाद और बढ़ गया

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। हयातुन निशा हत्याकांड में गिरफ्तार माणिक उद्दीन लस्कर और उसकी पत्नी भगवती माझी से पुलिस पूछताछ में हत्या की वजह त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद सामने आया है। पुलिस के अनुसार, माणिक और निशा के बीच करीब छह महीने से प्रेम संबंध था। निशा अपने पति से अलग रह रही थी।

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि 22 वर्षीय माणिक और 38 वर्षीय निशा के बीच संबंधों की जानकारी उसकी 21 वर्षीय पत्नी भगवती को हो गई थी। इसके बाद दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। गुड्डुवांचरी के किराए के मकान में तीनों साथ रहने लगे तो विवाद और बढ़ गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इसी वजह से निशा की हत्या की साजिश रची गई। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए। कुछ हिस्से बड़े बर्तनों में रखे गए, जबकि धड़ समेत अन्य हिस्से लाल रंग के ट्रॉली बैग में भरकर चेन्नई सेंट्रल से तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में रख दिए थे। गौरतलब है कि 5 अगस्त को आगरा कैंट पहुंची तमिलनाडु एक्सप्रेस में शव के टुकड़े मिलने पर जीआरपी ने जांच शुरू की थी। इसके बाद चेन्नई आरपीएफ ने चेन्नई रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। करीब 350 कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई थी, तब खुलासा हुआ। आरोपियों को इस बात का भरोसा नहीं था कि मामला ऐसे खुल जाएगा। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों चेन्नई से भागकर पूर्वोत्तर की ओर चले गए। मणिपुर से गिरफ्तारी के बाद उन्हें चेन्नई लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब प्रेम प्रसंग के अलावा पैसों के लेन-देन और हत्या की पूरी साजिश की भी जांच कर रही है।

ट्रॉली बैग में मिले थे मानव अंग

चेन्नई से नई दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस (12621) की जनरल बोगी में ट्रॉली बैग में मानव अवशेष से मिलने से आगरा कैंट स्टेशन पर सनसनी फैल गई थी। बैग से दुर्गंध उठने पर यात्री ने इसकी जानकारी दी थी। ट्रेन के आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचने पर जीआरपी ने बैग को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बैग चेन्नई से रखे जाने की आशंका थी। बैग में पॉलिथीन में लिपटे हुए मानव अंग मिले थे। पुलिस की जांच में सामने आया था कि शरीर के कुछ हिस्सों को मैदा और सब्जी में मिलाकर पकाया गया था। जीआरपी सीओ के अनुसार युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या की है।

निषाद पार्टी ने विमुक्त जनजाति को एससी सूची में शामिल करने की उठाई मांग

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। विमुक्त दिवस के अवसर पर निषाद पार्टी की ओर से विमुक्त जनजाति एवं निषाद वंश की उपजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि निषाद वंश की विभिन्न उपजातियां लंबे समय से सामाजिक एवं आर्थिक विसंगतियों का सामना कर रही हैं। संगठन ने मांग की कि जनगणना में निषाद वंश की सभी पर्यायवाची जातियों को एक साथ दर्ज किया जाए और जाति के कॉलम में संबंधित समुदाय का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। ज्ञापन में केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, मांझी, कश्यप, तुरहा, मछुआरा, रेकवार आदि को निषाद वंश की पर्यायवाची जातियां बताते हुए इनकी सही जनसंख्या दर्ज किए जाने की मांग की गई है। संगठन ने उत्तर प्रदेश में निषाद वंश की सभी पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने, विमुक्त जनजातियों के लिए शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने तथा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए निषाद समाज के लोगों के गांवों को 'आदर्श शहीद गांव' घोषित किए जाने की मांग भी रखी। ज्ञापन में केंद्र एवं प्रदेश सरकार के साथ-साथ संबंधित आयोगों से मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपील की गई है।इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेश कुमार निषाद, संगठन जिलाध्यक्ष रमेश निषाद पुर्व प्रधान, क्षत्रिय प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह, राष्ट्रीय सचिव केश कुमारी निषाद, प्रदेश सचिव बृजलाल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रेम चंद निषाद, रघुवीर निषाद प्रदेश सोशल मीडिया पज प्रभारी, हरिश्चंद्र निषाद, दुर्गेश मिश्रा आदि मौजूद रहे।

आधी रात घर में घुसे 4 बदमाश, 9 माह की मासूम को बंधक बनाकर लूटे 5 लाख के जेवर, मुंह बांधकर आए थे बदमाश

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। पीपीगंज थाना क्षेत्र के तिघरा गांव में सोमवार देर रात चार बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को धमकाते हुए करीब पांच लाख रुपये के जेवर लूट लिए। बदमाशों ने नौ माह की बच्ची को अपने कब्जे में लेकर परिवार पर दबाव बनाया। मासूम की सुरक्षा को देखते हुए उसकी मां ने घर में रखे आभूषण बदमाशों को सौंप दिए। वारदात के बाद आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गए।

तिघरा गांव निवासी प्रेमचंद के घर में परिवार के सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब एक बजे चार बदमाश मुंह बांधकर घर में घुसे। बताया जा रहा है कि उन्होंने घर के पीछे की ओर से प्रवेश किया। अचानक बदमाशों को सामने देखकर परिवार के लोग सहम गए।

बदमाशों ने नौ माह की मासूम को अपने कब्जे में लेकर परिवार को धमकाया और घर में मौजूद जेवर निकालकर देने को कहा। उन्होंने विरोध करने या शोर मचाने पर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

बच्ची की सुरक्षा के लिए मां ने सौंपे जेवर

मासूम की सुरक्षा को देखते हुए उसकी मां पूजा ने विरोध करने के बजाय बदमाशों की मांग पूरी करना बेहतर समझा। उन्होंने घर में रखे करीब पांच लाख रुपये कीमत के बताए जा रहे आभूषण बदमाशों को दे दिए। जेवर मिलने के बाद बदमाशों ने बच्ची को छोड़ दिया और मौके से भाग निकले।

पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

बदमाशों के जाने के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पीपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से वारदात के संबंध में जानकारी ली। बदमाशों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है। घटना के बाद तिघरा गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस अब बदमाशों के घर में प्रवेश करने के तरीके और वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

घर से दुर्गा पूजा का दानपात्र चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। धनपतगंज थाना पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत घर से दुर्गा पूजा का दानपात्र चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का दानपात्र तथा उसमें रखे 1210 रुपये बरामद किए हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, ग्राम पीरोसरैया निवासी दुर्गेश सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह ने 31 अगस्त 2026 को थाना धनपतगंज में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनके घर से दुर्गा पूजा का दानपात्र चोरी हो गया है, जिसमें करीब 1780 रुपये रखे थे। मामले में पुलिस ने बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी बल्दीराय के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष धनपतगंज के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने सुबह करीब 6.20 बजे ग्राम पड़रे से पीरोसरैया जाने वाली नहर पटरी पक्की रोड से आरोपी लालू प्रसाद पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम बेही निंदुरा, थाना बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद दानपात्र और 1210 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की और आरोपी को न्यायालय रवाना कर दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक राकेश कुमार मौर्य, हेड कांस्टेबल उमेश सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल मोहित कुमार तथा कांस्टेबल अवनीश कुमार शामिल रहे।

निमन्त्रण से लौट रहे बाप-बेटे की पिटाई कर रुपये छीने

भाई/सुल्तानपुर। धम्मौर थाना क्षेत्र के महेवा भाईं गांव मे निमंत्रण से लौट रहे बाप-बेटे की पिटाई कर छिनैती का मामला सामने आया है। आरोप है कि पास वाले गांव के लोगों ने मिलकर ऐसा किया। विरोध करने पर पीड़ितों से मारपीट की गई। पीड़ति ने मामले की लिखित तहरीर थाना धम्मौर में दी है। थाने पर महेवा भाईं निवासी प्रेम शंकर पांडे ने तहरीर दी है कि सोमवार रात करीब 8.30 बजे वह बेटे गौरव पाण्डेय के साथ अपनी कार में घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन ईट, गुम्मा व लाठी, डण्डो से हमला कर दिया। पीड़ति की गाड़ी के शीशे को तोड़ डाले और उसमें रखें बैग को जिसमे 23435रू० एवं अन्य आवश्यक कागजात थे छीन लिया। उक्त मामले मे थानाध्यक्ष विपेंद्र कुमार वर्मा ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

शरारती तत्वों ने आंबेडकर प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस अलर्ट

आर्यावर्त संवाददाता

बहेड़ी (बरेली)। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम भिलैया में शरारती तत्वों ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह प्रतिमा का दाहिना हाथ और चश्मा टूटा देखा तो गांव में तनाव फैल गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।

आंबेडकर पार्क में लगी है प्रतिमा

ग्राम भिलैया में गांव के बाहर सड़क किनारे करीब तीन बीघा भूमि पर आंबेडकर पार्क बना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क की चारदीवारी नहीं है। मंगलवार सुबह जब ग्रामीण पार्क पहुंचे तो उन्होंने

देखा कि प्रतिमा का दाहिना हाथ और चश्मा टूटा हुआ है। प्रतिमा क्षतिग्रस्त देख ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रतिमा का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जानकारी ली। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच की। घटना को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों की तलाश की जा रही है।

ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पार्क की चारदीवारी न होने से इस तरह की घटनाएं होती हैं। प्रशासन से पार्क की सुरक्षा और प्रतिमा की मरम्मत की मांग भी की गई है।

सीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

स्वाइन फ्लू से पीड़ित बदायूं के मरीज की मौत, बरेली के निजी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था उपचार

आर्यावर्त संवाददाता

बहेड़ी (बरेली)। स्वाइन फ्लू से पीड़ित बदायूं के एक मरीज की मौत हो गई। बिल्सी क्षेत्र निवासी 72 साल के मरीज का बरेली के एक निजी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। वह पहले से ही बीमार चल रहे थे। मेडिकल कॉलेज में हुई जांच रिपोर्ट में उनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। हालांकि जिले के विभागीय अफसरों का कहना है कि मरीज को अन्य बीमारी भी थी, जिसका वह उपचार करा रहे थे। स्वाइन फ्लू से मौत होने की पुष्टि विभाग नहीं कर रहा है। सीएमओ डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि जिले के आठ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें चार सक्रिय हैं। उपचार से तीन स्वस्थ्य हो गए हैं।

दिल्ली, अलीगढ़ में रह रहे हैं स्वाइन फ्लू से संक्रमित

बड़े शहरों में रह रहे जिले के लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आए हैं। इनमें से दो दिल्ली, दो अलीगढ़ और एक व्यक्ति ग्रेटर नोएडा में जांच के दौरान संक्रमित मिला है। संबंधित स्थानों पर ही उनका इलाज कराया जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमितों की जानकारी जुटाने के लिए उनके बताए पते और संबंधित स्थानों पर पहुंची, लेकिन जिले में कोई मरीज रहता हुआ नहीं मिला।

कोरोना काल की पीपीई किट हो चुकी हैं एक्सपायर

स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरणों को लेकर विभाग की चिंता बढ़ गई है। कोविड-19 के दौरान खरीदी गई पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) किट एक्सपायर हो चुकी है। ऐसे में अब स्वाइन फ्लू का मरीज सामने आने पर स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर विभाग के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। विभाग ने पीपीई किट, मास्क समेत अन्य जरूरी सुरक्षा सामग्री की मांग भेजी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वाइन फ्लू को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां तक कि जिला अस्पताल में एक वार्ड आरक्षित किया गया है। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी 20 बेड स्वाइन फ्लू के लिए आरक्षित किए गए हैं, ताकि संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे अलग रखकर उपचार दिया जा सके।

कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट और मास्क समेत सुरक्षा सामग्री खरीदी थी। उस समय इनका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के उपचार और संक्रमण से बचाव के लिए किया गया था। अभी स्वास्थ्य विभाग के पास 252 पीपीई किट मौजूद है, लेकिन इनको रखते हुए सात साल से ज्यादा समय हो गया है। ऐसे में लंबे समय बाद इन किटों की वैधता समाप्त हो चुकी है। ऐसे में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने पर पुरानी किटों के भरोसे स्वास्थ्यकर्मियों मरीज को पास भेजना खतरे से खाली नहीं है।

गंजेहड़ी पंचायत भवन में बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड, ग्रामीणों को मिल रही बड़ी सुविधा

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार/सुल्तानपुर। सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत गंजेहड़ी गांव के पंचायत भवन में ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को योजना का लाभ लेने के लिए दूर-दराज जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।

सीएचसी कुड़वार में तैनात उबैद हाशमी पंचायत भवन में बैठकर ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिल सकती है। पंचायत भवन में कार्ड बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ही

कार्ड बनने से उन्हें काफी सुविधा हो रही है और उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कुड़वार या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ग्रामीणों ने गांव में ही यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग और उबैद हाशमी का आभार जताया।

सुबह 5 बजे का पावर ऑवर क्यों है अहम? जानिए इसके फायदे

सुबह उठकर कुछ मिनट खुद के लिए बिताना एक ऐसी आदत है, जो आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकती है। इसे सुबह 5 बजे का पावर ऑवर कहा जाता है। इस घंटे में आप ध्यान, योग, पढ़ाई या किसी भी अन्य सकारात्मक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। यह समय आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आइए जानें कि सुबह 5 बजे का पावर ऑवर ह्यकैसे आपके जीवन को बदल सकता है।

मानसिक शांति और स्थिरता

सुबह का पावर ऑवर आपके दिमाग को शांत और स्थिर बना सकता है। जब आप सुबह सबसे पहले ध्यान या योग करते हैं तो आपके दिमाग की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है।

इससे आप पूरे दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और तनाव से भी दूर रहते हैं।

यह आदत आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और आपके विचारों को संतुलित रखती है।

शारीरिक सक्रियता

सुबह जल्दी उठकर कुछ मिनट व्यायाम करने से आपका शरीर सक्रिय रहता है। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि आपके शरीर में रक्त का प्रवाह भी बेहतर होता है।

नियमित व्यायाम से आपका ऊर्जा स्तर बढ़ता है और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं।

इसके अलावा यह आदत आपके शरीर को फिट रखने में भी मदद करती है और आपको स्वस्थ जीवन जीने का अवसर देती है।

सकारात्मक सोच विकसित करना

सुबह का समय सबसे शांत होता है, जब चारों ओर शांति होती है और कोई भी गतिविधि नहीं चल रही होती है। इस समय आप सकारात्मक सोच विकसित कर सकते हैं।

अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सकारात्मक सोच आपको उत्साहित और प्रेरित बनाए रखती है।

स्वास्थ्यवर्धक आहार ले पाना

सुबह जल्दी उठकर योग या ध्यान करने से आपके पेट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी भूख बढ़ती है और आप स्वस्थ नाश्ता करते हैं।

स्वस्थ नाश्ते से आपका पाचन तंत्र तेज होता है और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं।

इसके अलावा यह आदत आपको नियमित खाने की आदत डालने में मदद करती है, जिससे आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है और आप स्वस्थ रहते हैं।

सिर्फ थकान नहीं... कम नींद मांसपेशियों को भी कर सकती है कमजोर, एक्सपर्ट ने बताया

रोजाना नींद न पूरा होने पर थकान होती है। लोग इसे नॉर्मल प्रॉब्लम मान लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इससे हमारी मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर से समझें ऐसा क्यों होता है?

खराब नींद या स्लीप पैटर्न के ठीक न होने का असर सिर्फ थकान और चिड़चिड़ेपन तक सीमित नहीं रहता। इससे हमारी मांसपेशियों की अकड़न और जकड़न भी बढ़ सकती है। जिन लोगों की नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती है उन्हें अगले दिन गर्दन में दर्द-अकड़न परेशान करती है। पर क्या आप जानते हैं ऐसा होने पर कंधों में खिंचाव या मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है। कहा जाता है कि गलत पोजिशन में सोने से ऐसा होता है, पर एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे बचने के लिए पूरी नींद लेना भी जरूरी है।

अगर कोई रात में ठीक से सोता नहीं है तो शरीर की रिकवरी धीमी होने का कारण बन सकता है। चलिए आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं इससे प्रॉब्लम से जुड़ी जरूरी बातें...

सोने से शरीर को मिलता है रिकवरी का समय

डॉ। साइमन थॉमस (रोबोटिक जाइंट रिपलेस्टमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स हॉस्पिटल) के मुताबिक नींद वह समय है जब शरीर को दिनभर के शारीरिक तनाव से उबरने और टिश्यू की मरम्मत करने का मौका मिलता है। इसी दौरान शरीर की सूजन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और शारीरिक रिकवरी की प्रक्रिया में मदद मिलती है। जब नींद लगातार कम होती है या बार-बार टूटती है, तो शरीर की रिकवरी का ये प्रोसेस प्रभावित हो सकता है। ऐसे में कुछ लोगों को सुबह उठने पर मांसपेशियों में ज्यादा तनाव, दर्द या अकड़न महसूस हो सकती है।

बदलती लाइफस्टाइल भी बढ़ा रही समस्या

आज की मॉडर्न लाइफ इस समस्या को और आम बना रही है। देर रात तक स्क्रीन देखने की आदत, लंबे समय तक काम करना, सोने का समय लगातार बदलते रहना, तनाव और सुबह जल्दी उठने की मजबूरी, ये सभी नींद की टाइमिंग और उसकी क्वालिटी को कम कर सकते हैं। जो लोग कई घंटे लगातार डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, वे खासतौर पर इसकी चपेट में आ सकते हैं। लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि न होने से पहले ही गर्दन, कंधों, पीठ और कूल्हों में जकड़न महसूस हो सकती है।

खराब नींद और मांसपेशियों की अकड़न एक साइकिल

खराब नींद और शरीर में होने वाली तकलीफ एक-दूसरे को बढ़ा सकती हैं। मांसपेशियों में दर्द या असहजता के कारण व्यक्ति को आरामदायक तरीके से सोने में परेशानी हो सकती है। वहीं, पर्याप्त नींद न मिलने पर अगले दिन शरीर दर्द और असहजता के प्रति ज्यादा संवेदनशील महसूस कर सकता है। इस तरह मांसपेशियों की तकलीफ और खराब नींद एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए एक चक्र बना सकते हैं।

मांसपेशियों की अकड़न दूर करने के लिए क्या करें?

इसके लिए जरूरी नहीं कि हमेशा जटिल उपायों की जरूरत पड़े। रोजाना सोने और जागने का समय लगभग एक जैसा रखने से मदद मिल सकती है। सोने से पहले ऐसी स्क्रीन गतिविधियों को सीमित करना भी फायदेमंद हो सकता है जो दिमाग को ज्यादा सक्रिय या उत्तेजित करती हैं।

दिन के समय शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और लंबे समय तक लगातार बैठे रहने के बजाय बीच-बीच में चलने-फिरने या मूवमेंट ब्रेक लेना भी शरीर की रिकवरी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सुबह उठने के बाद हल्की स्ट्रेचिंग भी थोड़े समय के लिए होने वाली मांसपेशियों की अकड़न और जकड़न को कम करने में मदद कर सकती है।

अपने दिनचर्या में शामिल करें बैडमिंटन, इसे खेलने से मिल सकते हैं कई लाभ

बैडमिंटन एक ऐसा खेल है, जो न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। यह खेल शरीर को सक्रिय रखता है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा बैडमिंटन खेलने से शारीरिक सहनशक्ति में भी सुधार होता है। इस खेल के माध्यम से आप अपनी गति, संतुलन और तालमेल को भी सुधार सकते हैं। आइए जानते हैं कि बैडमिंटन खेलने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

बैडमिंटन खेलने से दिल की धड़कनें तेज होती हैं, जिससे शरीर में खून का संचार बेहतर होता है। यह खेल दिल की सेहत को बढ़ावा देता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से बचाव कर सकता है।

नियमित रूप से बैडमिंटन खेलने वालों में दिल की बीमारी का खतरा कम होता है।

इसके अलावा यह खेल शरीर में खून के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे दिल को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और यह स्वस्थ रहता है।

मानसिक तनाव से राहत

बैडमिंटन खेलने से मानसिक तनाव कम होता है। जब आप इस खेल को खेलते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से खेल पर केंद्रित हो जाता है, जिससे आपके दिमाग को आराम मिलता है।

यह खेल खुश रहने वाले हार्मोन का उत्पादन बढ़ाता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को दूर करता है।

इसके अलावा बैडमिंटन खेलने से आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं।

वजन नियंत्रित करने में सहायक

बैडमिंटन एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो कैलोरी जलाने में बहुत प्रभावी होता है। नियमित रूप से बैडमिंटन खेलने से आपका वजन नियंत्रित रहता है और मोटापे का खतरा कम होता है।

यह खेल शरीर की ऊर्जा को तेज करता है, जिससे शरीर में चर्बी कम होती है और फिटनेस बढ़ती है।

इसके अलावा बैडमिंटन खेलने से शरीर की सहनशक्ति भी बढ़ती है, जिससे आप अधिक सक्रिय और स्वस्थ महसूस करते हैं।

शारीरिक सहनशक्ति में सुधार

बैडमिंटन खेलने से शरीर की सहनशक्ति बढ़ती है। इस खेल को खेलने के दौरान तेज दौड़ना, कूदना और तेजी से शटल को मारना पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में मजबूती आती है।

नियमित रूप से बैडमिंटन खेलने वालों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनका शरीर अधिक सक्रिय रहता है।

इसके अलावा बैडमिंटन खेलने से शरीर की लचीलापन भी बढ़ती है, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है।

सामाजिक संबंधों को बढ़ावा

बैडमिंटन एक ऐसा खेल है, जिसे आप अकेले या दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और आपसी समझ बढ़ती है।

दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने का यह एक अच्छा तरीका है।

इस तरह बैडमिंटन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी है।

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है वीगन पिज्जा, जानिए इसे बनाने की रेसिपी

पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद है। अगर आप वीगन हैं और सोचते हैं कि घर पर वीगन पिज्जा बनाना मुश्किल है तो ऐसा नहीं है। इस लेख में हम आपको एक आसान और झटपट बनने वाले वीगन पिज्जा की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को अपनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।

पिज्जा बेस बनाने का तरीका

सबसे पहले पिज्जा बेस तैयार करें। इसके लिए आपको मैदा, पानी, नमक और थोड़ा-सा तेल चाहिए।

एक बड़े कटोरे में मैदा, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाएं। फिर इसमें धीरे-धीरे पानी डालें और गूंथ लें, जब तक कि आटा नरम न हो जाए।

अब इस आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रखें, ताकि यह थोड़ा फूल जाए। इसके बाद इसे बेलकर गोल आकार दे दें, जिससे आपका पिज्जा बेस तैयार हो जाएगा।

पिज्जा सॉस कैसे बनाएं?

पिज्जा सॉस के लिए आपको टमाटर, प्याज, लहसुन, नमक और थोड़ी-सी अजवायन चाहिए। सबसे पहले टमाटर और प्याज को बारीक काट लें।

अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें लहसुन भूनें। फिर इसमें टमाटर और प्याज डालकर पकाएं, जब तक कि वे नरम न हो जाएं।

इसके बाद इसमें नमक और अजवायन मिलाएं और 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि सॉस गाढ़ा हो जाए। आपका पिज्जा सॉस तैयार हो जाएगा।

सब्जियों को कैसे तैयार करें?

पिज्जा के लिए सब्जियां चुनते समय अपनी पसंद के अनुसार ही सब्जियों का चयन करें। आप शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मशरूम और जैतून का उपयोग कर सकते हैं।

सबसे पहले सभी सब्जियों को बारीक काट लें, ताकि पिज्जा पर समान रूप से फैल सकें। अगर आप चाहें तो सब्जियों को थोड़ा भून भी सकते हैं, ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए।

इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें सभी सब्जियों को मिलाकर कुछ मिनट तक पकाएं।

पिज्जा को बेक करें

अब बारी आती है पिज्जा को बेक करने की। इसके लिए ओवन को 220 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म करें।

इसके बाद पहले पिज्जा बेस पर थोड़ा-सा पिज्जा सॉस फैलाएं और फिर ऊपर से कटी हुई सब्जियां डालें।

अब तैयार पिज्जा को पहले से गर्म किए ओवन में रखें और लगभग 15-20 मिनट तक बेक करें, जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए।

परोसने से पहले इस पर चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो का छिड़काव करना न भूलें।

वित्तमंत्री सीतारमण ने भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने पर दिया जोर

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी 3एम से भारत में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकास में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहां व्यापक अवसर उपलब्ध हैं।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने यह बात अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एशविल में आयोजित जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान 3एम के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विलियम ब्राउन के साथ हुई बैठक में कही। यह मुलाकात बैठक के इतर आयोजित विभिन्न द्विपक्षीय कार्यक्रमों का हिस्सा थी।

दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3एम की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार-आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है।

मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान डेटा सुरक्षा, तकनीकी विकास तथा भारतीय प्रतिभा को घरेलू औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पास कुशल मानव संसाधन, मजबूत विनिर्माण क्षमता और तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक ढांचा है, जिसका लाभ उठाकर 3एम अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों का विस्तार कर सकती है।

निर्मला सीतारमण ने 3एम से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विस्तार करने और नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत में विकसित नवाचार केवल घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी मजबूत कर सकते हैं।

उन्होंने कंपनी से उन्नत विनिर्माण क्षमताओं, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क और आरएंडडी केंद्रों में निवेश बढ़ाने की अपील की। वित्त मंत्री का कहना था कि भारत की बढ़ती औद्योगिक क्षमता और विशाल प्रतिभा आधार वैश्विक कंपनियों को दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकता है।

वहीं 3एम के चेयरमैन एवं सीईओ विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में प्रौद्योगिकी विकास और स्थानीय बाजार दोनों के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। ब्राउन ने भारत सरकार द्वारा आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से उद्योगों को दिए जा रहे समर्थन की भी प्रशंसा की।

वित्त मंत्री ने 3एम द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में जताए गए विश्वास का स्वागत किया और कंपनी की भारत में मौजूदगी को और विस्तार देने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वैश्विक कंपनियों के लिए एक अनुकूल और प्रतिस्पर्धी कारोबारी वातावरण तैयार करने के लिए लगातार सुधारों पर काम कर रही है।

गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण अगले दो दिनों तक एशविल में जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक तथा उससे जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वह दक्षिण कैरोलिना के ग्रीनविल-स्पार्टनबर्ग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचीं, जहां अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने उनका स्वागत किया।

हर महीने टाइम पर ईएमआई भरने के बाद भी खराब हो रहा आपका क्रेडिट स्कोर? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां

30% से अधिक क्रेडिट कार्ड खर्च आपको बैंक की नजर में रिस्की बनाता है

लाखों लोग इस बात से परेशान हैं कि हर किस्त समय पर चुकाने के बावजूद उनका सिबिल स्कोर कम क्यों हो रहा है। दरअसल सिबिल आपकी पूरी वित्तीय आदतों का रिपोर्ट कार्ड है, जहां एक चूक भी भारी पड़ती है।

आज लाखों लोग एक अजीब परेशानी का सामना कर रहे हैं। वे अपनी हर EMI समय पर चुकाते हैं, कोई किस्त बाउंस नहीं होती, फिर भी उनका क्रेडिट स्कोर(Credit Score) अचानक नीचे आ जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर गलती कहां हो रही है। दरअसल क्रेडिट स्कोर सिर्फ किस्तों के भुगतान से तय नहीं होता। ये आपकी पूरी फाइनेंशियल आदतों का एक आईना होता है। अगर आप कुछ बारीक गलतियां कर रहे हैं, तो आपका स्कोर चुपचाप गिरता रहेगा। आगे चलकर आपको लोन रिजेक्शन या फिर महंगे ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जो आपका Credit Score खराब कर रही हैं।

क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल

अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपये है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर महीने 80-90 हजार खर्च कर दें। बैंक इसे आपके ऊपर 'ओवर डिपेंडेंसी' मानते हैं। नियम के मुताबिक आपको अपनी लिमिट का सिर्फ 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका खर्च 70 प्रतिशत के पार जा रहा है, तो बैंक के सिस्टम में आपके लिए एक रिस्क सिग्नल जनरेट हो जाता है। इससे आपका स्कोर सीधे तौर पर प्रभावित होता है।

बार-बार लोन के लिए अप्लाई करना

कई बार लोग एक साथ कई बैंकों में लोन के लिए आवेदन कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं से अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो हर बार आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर एक "हार्ड इंक्वायरी" दर्ज होती है। इससे बैंकों को लगता है कि आपको तुरंत पैसों की सख्त जरूरत है। आपकी प्रोफाइल रिस्की लगने लगती है। इसका सीधा असर आपके स्कोर पर पड़ता है।

पुराने क्रेडिट कार्ड खाते बंद करना

अक्सर लोग अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल न करने पर बंद करवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। पुराना अकाउंट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मजबूत बनाता है। जब आप उसे बंद करते हैं, तो आपकी 'क्रेडिट उम्र' कम हो जाती है। क्रेडिट स्कोर का 30 फीसदी हिस्सा पेमेंट हिस्ट्री पर निर्भर करता है। पुरानी हिस्ट्री मिटने से आपकी प्रोफाइल कमजोर हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पास सिर्फ पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन हैं, तो भी स्कोर गिर सकता है। बेहतर स्कोर के लिए अनसिक्योर्ड के साथ सिक्योर्ड लोन का बैलेंस होना भी जरूरी है।

रिपोर्ट में छिपी अनजाने गलतियां

कई बार आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी सिस्टम की गड़बड़ी से स्कोर गिर जाता है। ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का लोन आपके नाम पर दर्ज हो गया हो। या फिर आपका कोई पुराना बंद हो चुका लोन अभी भी एक्टिव दिख रहा हो। गलत बकाया एंट्री भी इसका एक बड़ा कारण है। इसलिए हर 3 से 6 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें। आजकल बैंक एआई बेस्ड स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां छोटी सी लापरवाही भी तुरंत पकड़ी जाती है। अच्छे स्कोर के लिए 750 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। इसके लिए खर्च लिमिट में रखें।

ट्रंप प्रशासन में बड़ा बदलाव : अमेरिकी सेना के सचिव ड्रिस्कॉल का इस्तीफा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सीएनएन ने मामले से परिचित तीन सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सीएनएन के अनुसार, एक सूत्र ने बताया कि ड्रिस्कॉल और युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ के बीच तनाव को देखते हुए उनका यह फैसला हैरान करने वाला नहीं था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने ड्रिस्कॉल के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ड्रिस्कॉल ने उत्कृष्ट नेतृत्व करने के साथ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में भी मदद की। हालांकि, ड्रिस्कॉल के इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया गया है। यह सैन्य नेतृत्व में बदलाव की एक और कड़ी है। खास तौर पर अमेरिकी सेना में हाल के दिनों में बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। केली ने कहा, 'सचिव ड्रिस्कॉल ने सेना विभाग में राष्ट्रपति ट्रंप के 'मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन' एजेंडे को आगे बढ़ाने में बेहद प्रभावी भूमिका निभाई। उन्होंने ऐतिहासिक सैन्य अभियानों के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व दिया, सैन्य तैयारी और युद्धक क्षमता पर फिर से जोर दिया, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में मदद की और कई अन्य काम किए।'

अमेरिकी प्रसारक के अनुसार, ड्रिस्कॉल का इस्तीफा हेगसेथ के साथ कई महीनों से चल रहे मतभेद के बाद आया है। यह ऐसे समय भी हुआ है, जब ईरान के साथ युद्ध को छह महीने हो चुके हैं। सीएनएन ने बताया कि हेगसेथ ने इस साल की शुरुआत में सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज और दो अन्य जनरलों को पद से हटा दिया था। जॉर्ज और ड्रिस्कॉल एक-दूसरे के साथ करीबी तौर पर काम करते थे। ड्रिस्कॉल पूर्व आर्मी रेंजर और वेंचर कैपिटल निवेशक रहे हैं। उन्होंने सैन्यकर्मियों के लिए बेहतर जीवन स्थितियों, उपकरणों के आधुनिकीकरण और युद्ध में यूक्रेनी बलों द्वारा व्यावसायिक तकनीक के इस्तेमाल से मिली सीख को अपनाने की वकालत की। उनके नेतृत्व में निजी कंपनियों ने अमेरिकी सेना के ठिकानों पर डेटा सेंटर, महत्वपूर्ण खनिजों की रिफाइनरी और भोजन की सुविधाएं विकसित करने के लिए 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश का वादा किया था। सीनेट ने 25 फरवरी 2025 को 66-28 मतों से ड्रिस्कॉल के नाम की पुष्टि की थी। इससे पहले ट्रंप ने उन्हें सेना सचिव के पद के लिए नामित किया था और पूर्व सैनिक, निवेशक तथा राजनीतिक सलाहकार के तौर पर उनके अनुभव को रेखांकित किया था।

2028 राष्ट्रपति चुनाव: हेगसेथ के नाम की अटकलों पर ट्रंप ने लगाया विराम, बोले- अभी बहुत जल्दी है, पहले मिडटर्म

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की अटकलों को फिलहाल खारिज करते हुए कहा कि इस बारे में बात करना अभी बहुत जल्दबाजी है। ट्रंप ने जोर दिया कि पार्टी और सरकार का ध्यान पहले आगामी मिडटर्म चुनावों पर होना चाहिए।

ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि हेगसेथ शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन 2028 के चुनाव को लेकर चर्चा के लिए अभी काफी समय है। उन्होंने कहा पहले हमें मिडटर्म चुनावों से गुजरना होगा। ट्रंप ने

हेगसेथ को बहुत अच्छे व्यक्ति के तौर पर बताया और कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में 2028 के लिए संभावित उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। उनके मुताबिक, कई ऐसे लोग भी चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे होंगे, जिनके नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं।

अभी किस पर ध्यान दे रहे हैं हेगसेथ?

ट्रंप ने कहा कि इस समय हेगसेथ का पूरा ध्यान सेना की तैयारियों और अमेरिकी सैनिकों की जरूरतों पर है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हेगसेथ की प्राथमिकता सैन्य मामलों पर ही केंद्रित है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशों में हालिया सैन्य अभियानों का जिक्र करते हुए वेनेजुएला और ईरान में अमेरिकी कार्रवाई का भी उल्लेख किया और दावा किया कि वहां अमेरिका अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

2028 की खबर पर हेगसेथ ने क्या कहा था?

ट्रंप की टिप्पणी से पहले पीट हेगसेथ ने एनबीसी न्यूज की उस रिपोर्ट को खारिज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हेगसेथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रिपोर्ट को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र काम अमेरिकी रक्षा विभाग को मजबूत बनाना है और वह इसी जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

क्यों अहम है ट्रंप का बयान?

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अगले चुनाव को लेकर राजनीतिक अटकलें अक्सर समय से पहले शुरू हो जाती हैं। हालांकि, ट्रंप और हेगसेथ दोनों की ओर से 2028 की चर्चा को फिलहाल खारिज किए जाने से संकेत मिलता है कि रिपब्लिकन नेतृत्व का सार्वजनिक फोकस आगामी मिडटर्म चुनाव और रक्षा प्राथमिकताओं पर बनाए रखने की कोशिश है।

हूती और अलकायदा के बीच गठबंधन? यमन से सोमालिया तक बढ़ा आतंकी नेटवर्क

यमन। यमन के हूती विद्रोहियों और अलकायदा से जुड़े सोमालिया के आतंकी संगठन अल-शबाब के बीच हथियारों की सप्लाई और सहयोग का एक नेटवर्क सामने आया है। इस नेटवर्क में यमन से मिलिट्री लेवल के हथियार सोमालिया तक पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। माना जा रहा है कि इस तरह का सहयोग दोनों संगठनों को अपने-अपने फायदे पूरे करने में मदद कर सकता है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस नेटवर्क में जिब्रिल 'वन-आर्म्ड' याह्या अली नाम के एक सोमाली व्यक्ति की भूमिका सामने आई है। वह यमन से हथियार खरीदकर उन्हें सोमालिया में अल-शबाब तक पहुंचाता था। रिपोर्ट के मुताबिक, जिब्रिल ने यमन के अल-

गायदा इलाके में एक हथियार कारोबारी की मदद से हूती विद्रोहियों से मिलिट्री लेवल के हथियार हासिल किए थे।

अल-शबाब सोमालिया में एक्टिव एक इस्लामिस्ट विद्रोही संगठन है और अलकायदा से जुड़ा हुआ है। संगठन के पास पैसे और दूसरे संसाधन हैं, लेकिन उसे हथियारों, ट्रेनिंग और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जरूरत रहती है। वहीं, हूतियों के पास आधुनिक हथियारों और मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक पहुंच है, लेकिन उन्हें पैसे और यमन के बाहर नए नेटवर्क की जरूरत हो सकती है। यही जरूरत दोनों संगठनों के बीच संभावित सहयोग की वजह बन सकती है। हथियारों की सप्लाई के बदले हूतियों को आर्थिक फायदा और अफ्रीका में एक नया नेटवर्क मिल सकता है, जबकि अल-शबाब को आधुनिक हथियार और अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

लाल सागर और अदन की खाड़ी पर असर

इस संभावित सहयोग का सबसे बड़ा असर लाल सागर और अदन की खाड़ी के आसपास देखने को मिल सकता है। यमन और सोमालिया के बीच का यह समुद्री इलाका पहले से ही स्ट्रैटेजिक तौर पर बेहद अहम है। हूती नेटवर्क अगर सोमालिया में अल-शबाब जैसे संगठनों तक अपनी पहुंच बढ़ाता है, तो पश्चिमी देशों और उनके हितों के खिलाफ हमलों का खतरा बढ़ सकता है।

हूती और अलकायदा के बीच विचारधारा और क्षेत्रीय हितों को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। इसलिए इसे अभी सीधे तौर पर औपचारिक 'हूती-अलकायदा गठबंधन' कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि, हथियारों की सप्लाई और दोनों से जुड़े नेटवर्क के बीच संपर्क इस बात का संकेत देता है कि साझा फायदे के लिए सीमित सहयोग की गुंजाइश बन रही है। अगर यह नेटवर्क आगे मजबूत होता है, तो इसका असर यमन और सोमालिया से बाहर पूरे लाल सागर रीजन की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है।

रेप के दोषी भारतीय मूल के गुरमीत सिंह की US नागरिकता रद्द, काट रहा 20 साल की सजा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने रेप के दोषी भारतीय मूल के एक व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर दी है। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप के दोषी गुरमीत सिंह की नेचुरलाइजेशन (नागरिकता पाने की प्रक्रिया) को रद्द करने का फैसला सुनाया। भारत का रहने वाला गुरमीत सिंह फरवरी 1992 में छह महीने से कम समय के लिए विजिटर के तौर पर अमेरिका आया था। इसके बाद वह बिना इजाजत के कई सालों तक अमेरिका में रहा, जब तक कि जून 2000 में फैमिली-बेस्ड इमिग्रेंट वीजा अर्जी के जरिए उन्हें स्थायी निवासी का दर्जा नहीं मिल गया। अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि भारत के रहने वाला और रेप का दोषी गुरमीत सिंह अब अमेरिकी नागरिक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुरमीत ने नागरिकता पाने की प्रक्रिया के दौरान रेप और अपहरण की बात छिपाई थी, और अब एक फ़ेडरल कोर्ट ने उनकी नागरिकता रद्द कर दी है। ब्लैंच ने आगे कहा कि अमेरिकी नागरिकता अपराधियों के लिए कोई ढाल नहीं है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी से हासिल की गई नागरिकता अपराधियों को सजा से नहीं बचा पाएगी। जस्टिस डिपार्टमेंट के सिविल डिवीजन के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ब्रेट शुमेट ने कहा कि गुरमीत सिंह ने भयानक आपराधिक कामों को छिपाकर गैर-कानूनी तरीके से अमेरिकी नागरिकता के फायदे हासिल किए थे। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी जोसेफ नोसेला जूनियर ने कहा कि कोर्ट का फ़ैसला, जिसके तहत आरोपी को गलत तरीके से हासिल की गई नागरिकता छोड़नी होगी, उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो धोखे से नागरिकता हासिल करते हैं।

लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिरी: चिदंबरम ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- 1975 के बाद सबसे कम स्कोर कैसे?

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने मंगलवार को वी-डेम के 'चुनावी लोकतंत्र सूचकांक' में 179 देशों में भारत की 106वीं रैंक की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि यह 1975 के बाद से सूचकांक में सबसे निचला स्कोर है।

चिदंबरम ने एक्स पर पोस्ट किया, 'चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 179 देशों में 106वें स्थान पर है। भारत के लिए वी-डेम का लोकतंत्र सूचकांक स्कोर 1975 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है।' कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरती रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई मौकों पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। वी-डेम ने चुनावी लोकतंत्र सूचकांक पर वर्ष 2025 के लिए भारत को 0.38 का स्कोर दिया है, जिससे देश 106 वें स्थान पर है। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत 0.26 के स्कोर के साथ 105वें स्थान पर है।

कैसे स्कोर देता है वी-डेम?

वी-डेम जनसंख्या-भारित उपायों का उपयोग करता है, जो यह दर्शाता है कि औसत वैश्विक नागरिक सांख्यिकीय रूप से किस हद तक लोकतंत्र का आनंद लेता है। यह देश के औसत का उपयोग करके सेशेल्स या तिमोर-लेस्ते जैसे छोटे देशों में हुई प्रगति को भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका के समान महत्व देता है। इस संस्थान ने भारत को चुनावी तानाशाही की श्रेणी में रखा है।

भारत को किस श्रेणी में रखा गया है?

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण और मध्य एशिया में, नेपाल और श्रीलंका में केवल 2 प्रतिशत लोग ही चुनावी लोकतंत्र का लाभ उठा पाते हैं। वहीं, बहुत ही कम संख्या में लोग भूटान, मंगोलिया और मालदीव जैसे तीन ग्रे जोन' वाले लोकतंत्रों में रहते हैं। इसने भारत को किर्गिस्तान और पाकिस्तान के साथ चुनावी तानाशाही वाली श्रेणी में रखा है। जबकि अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को बंद तानाशाही वाले देशों के तौर पर वर्गीकृत किया है। भारत में, वी-डेम पार्टी 2009 से धीरे-धीरे तानाशाही के उदय की वकालत करती है। लोकतांत्रिक संस्थानों के व्यवस्थित विघटन का दावा करती है। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता में गिरावट, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के उत्पीड़न और नागरिक समाज तथा विपक्ष पर हमलों को इस गिरावट के कारणों के रूप में उजागर किया। वी-डेम इंस्टीट्यूट का नेतृत्व एसोसिएट प्रोफेसर स्टीवन विल्सन कर रहे हैं। यह स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में स्थित है।

बजरंग दल से भिड़ने वाले 'मोहम्मद' दीपक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआईआर पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून के जिम मालिक 'मोहम्मद' दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। यह मामला बजरंग दल मुस्लिम के सदस्यों और एक दुकानदार के बीच कथित विवाद से जुड़ा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश के अमल पर भी रोक लगा दी, जिसमें दीपक को घटना से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट या विडियो डालने से प्रतिबंधित किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दीपक की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा। दीपक ने हाई कोर्ट के एफआईआर रद्द करने से इनकार के फैसले को चुनौती दी है। दीपक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल एक दुकानदार की मदद करने के लिए वहां गए थे। उन्होंने दावा किया कि बजरंग दल के सदस्यों ने दुकान के नाम में 'बाबा' शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। भीड़ ने दीपक से नाम पूछा तो उन्होंने 'मोहम्मद दीपक' बताया। सिंघवी ने कहा कि दीपक ने भी शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

'नेक मददगार' की दलीलः दीपक कुमार की पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल केवल एक दुकानदार की सहायता के लिए आगे आया था। उन्होंने सवाल उठाया कि एक 'नेक मददगार' के खिलाफ इस तरह की आपराधिक शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है।

'विश्वनाथ एंड सन्स' ने 16 दिनों में कमाए 240 करोड़ रुपये, दुनियाभर में छाया फिल्म का जलवा

अभिनेता सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रही है। फिल्म के आधिकारिक पोस्टर के मुताबिक, रिलीज के महज 16 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 240 करोड़ रुपये की सकल कमाई कर ली है। वेंकी अटुलुरी के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

फिल्म में रोमांस, हास्य, भावनाओं और व्यावसायिक मनोरंजन का संतुलित मिश्रण देखने को मिलता है। रिलीज के बाद से ही फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और यह इस सत्र की तेलुगु फिल्मों में एक मजबूत प्रदर्शन करने वाली फिल्म के रूप में उभरी है।

बताए गए कारोबार के आंकड़ों के अनुसार, 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने भारत में लगभग 180 करोड़ रुपये की सकल कमाई की है, जबकि विदेशी बाजारों से करीब 60 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस तरह फिल्म की कुल दुनियाभर की कमाई 240 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

भाषा के आधार पर भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तेलुगु संस्करण से करीब 110 करोड़ रुपये, जबकि तमिल संस्करण से लगभग 70 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। दोनों भाषाओं से फिल्म की कुल भारतीय सकल कमाई करीब 180 करोड़ रुपये बताई गई है।

विदेशी बाजारों में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिला है। उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने करीब 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 27 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। वहीं, अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से लगभग 34 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।

फिल्म को पारिवारिक दर्शकों की अच्छी संख्या का लाभ मिला है। दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और सिनेमाघरों में लगातार अच्छी दर्शक उपस्थिति के चलते फिल्म शुरुआती सप्ताहांत के बाद भी अपनी रफ्तार बनाए रखने में सफल रही है।

वेंकी अटुलुरी द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में सूर्या और ममिता बैजू मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रही हैं।

फिल्म का निर्माण नागा वामसी और साई सौजन्य ने किया है। यह सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फोर सिनेमाज की प्रस्तुति है।

फिल्म के डिजिटल प्रसारण अधिकार कथित तौर पर नेटफ्लिक्स के पास हैं। हालांकि, इसके डिजिटल प्रीमियर की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म के सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में डिजिटल मंच पर प्रदर्शित होने की संभावना है।

बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपये की दुनियाभर की सकल कमाई के साथ 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई कहां तक पहुंचती है, इस पर अब फिल्म कारोबार से जुड़े लोगों और दर्शकों की नजर बनी हुई है।

अक्षय ओबेरॉय की फिल्म लव लॉटरी का पहला लुक जारी

एक्टर अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला स्टारर और सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म लव लॉटरी का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। महज 49 सेकंड का यह वीडियो अपने रहस्यमयी अंदाज, दमदार विजुअल्स और सस्पेंस से भरपूर बैकग्राउंड स्कोर के साथ दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रहा है। फिल्म कोर्टरूम ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर का दिलचस्प मिश्रण है, जिसमें रिश्तों, कानून और समाज के कई संवेदनशील पहलुओं को कहानी का हिस्सा बनाया गया है।

फर्स्ट लुक में कहानी का ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म के प्रमुख किरदारों की झलक दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी है। इसमें अक्षय ओबेरॉय, हेली दरूवाला, कबीर दुहान सिंह, हेमंत पांडे, विजयंत कोहली और अग्नि अग्यारी अपने अलग-अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो के आखिर में संतोष शुक्ला की एंट्री कहानी के रहस्य को और गहरा कर देती है। फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और हेली दरूवाला के अलावा कबीर दुहान सिंह, विजयंत कोहली, हेमंत पांडे, इंदिरा कृष्णन, संतोष शुक्ला, विक्रम शर्मा, अग्नि अग्यारी, कुमार सौरभ, अश्वंत लोढ़ी और अर्शदीप संधू अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 18 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली लव लॉटरी एक ऐसे आधुनिक शहरी कपल की कहानी है, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में आई दरार धीरे-धीरे एक जटिल कानूनी लड़ाई में बदल जाती है।

इसी बीच एक मर्डर मिस्ट्री, कई चौंकाने वाले खुलासे कहानी को नए मोड़ देती हैं। फिल्म रिश्तों में विश्वास, सामाजिक धारणा, भावनात्मक शोषण और गंभीर आरोपों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे विषयों को भी छूती है। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है। प्राकृतिक वादियों और मनमोहक दृश्यों को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल एक्सपीरियंस और भी शानदार बन गया है। फिल्म के निर्माता कुलदीपदरूवाला उर्फ तुषार ने कहा, हम चाहते थे कि लव लॉटरी सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म न बने, बल्कि दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करे। इसमें सस्पेंस, इमोशंस और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों का ऐसा मेल देखने को मिलेगा जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा। वहीं, निर्देशक अरविंद पांडे ने कहा, यह सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि रिश्तों, इमोशन और सच्चाई की तलाश की कहानी है। हमने मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस और इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को इस तरह पिरोया है कि दर्शक आखिरी दृश्य तक अनुमान लगाते रहेंगे कि सच क्या है।

लव लॉटरी का निर्माण सिनेमा गंज फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। फिल्म के निर्माता कुलदीप भार्गव (तुषार), निर्देशक अरविंद पांडे और लेखक अंकुर खत्री हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी नवीन वी। मिश्रा ने और एडिटिंग प्रकाश झा ने की है, जबकि संगीत वरुण मिश्रा और अरविंद पांडे ने तैयार किया है।

खतरों के खिलाड़ी 15 से जल्दी बाहर होने का दर्द अब भी दिल में है: अविका गौर

अभिनेत्री अविका गौर ने खतरों के खिलाड़ी 15 से अपने एलिमिनेशन के बाद पहली बार अपने अनुभव और भावनाओं के बारे में खुलकर बात की है। शो से इतनी जल्दी बाहर होना उनके लिए आसान नहीं रहा। अविका ने कहा कि एलिमिनेशन के बाद जब वह घर बैठकर शो देखती हैं, तो उनके मन में बार-बार यही ख्याल आता है कि अगर वह उस वक्त वहां होतीं, तो शायद और बेहतर कर सकती थीं।

हालांकि, बाद में उन्हें यह भी एहसास होता है कि टीवी पर बैठकर किसी स्टंट को देखना और खुद उस डर, दबाव और एड्रेनालिन के बीच उसे करना बिल्कुल अलग बात है। अविका गौर ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया और बताया कि खतरों के खिलाड़ी ने उनकी जिंदगी और खुद को देखने के नजरिए पर काफी असर डाला है।

उन्होंने लिखा, मैंने खतरों के खिलाड़ी देखने के बाद अपने बारे में एक बात महसूस की है। मैं खुद को यह सोचते हुए पाती हूं कि अगर मैं वहां होती, तो मैंने हार नहीं मानी होती। मैं और ज्यादा कोशिश करती। मैं बेहतर करती। अविका ने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, शो को आराम से सोफे पर बैठकर देखने के दौरान मुझे ऐसा लगने लगता है, जैसे मैं खतरों के खिलाड़ी की एक्सपर्ट बन गई हूं।

लेकिन फिर याद आता है कि मैं अपनी जिंदगी के आरामदायक माहौल में बैठकर शो देख रही हूं। मुझे न तो उस समय का दबाव महसूस हो रहा है और न ही उस स्टंट को करने का डर। बाहर बैठकर किसी स्थिति का हीरो बनना बहुत आसान है। जब कोई चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो हम उसे बार-बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, अलग-अलग फैसलों की कल्पना करते हैं और कहानी का एक ऐसा वर्जन बना लेते हैं, जो कभी हुआ ही नहीं।

अविका ने कहा, शायद इसी वजह से इतनी जल्दी एलिमिनेट होना मेरे लिए पूरी तरह छोड़ पाना मुश्किल रहा है। मेरे अंदर कहीं न कहीं अभी भी वह लड़की है, जो सोचती है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ था। शायद सच में था भी। लेकिन मुझे यह भी समझना होगा कि इस सोच में लगातार जीते रहना सही नहीं है। यह मानना अलग बात है कि आपके पास और बेहतर करने की क्षमता थी और हर वक्त उस दुनिया में रहना अलग।

उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार शो किया था, तब मैं सिर्फ 21 साल की थीं। उस समय शो ने मुझे खुद को और अपने भविष्य को एक अलग नजरिए से देखने में मदद की थी। मैं डर का सामना करने और स्टंट करने के इरादे से शो में गई थीं, लेकिन वहां से निकलने के बाद मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ नया समझ आया।

अविका ने लिखा, मैंने हमेशा मेहनत करने, तैयारी करने, खुद को आगे बढ़ाने और अपनी पसंद की जिंदगी बनाने में विश्वास किया है।

इसलिए ऐसी चीज को स्वीकार करना, जो पूरी तरह मेरे नियंत्रण से बाहर हो, मेरे लिए मुश्किल और सच कहूं तो दिल तोड़ने वाला रहा है। उन्होंने आगे कहा, कई बार इंसान किसी चीज के लिए अपना सब कुछ दे देता है, फिर भी नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा उसने सोचा था। शायद क्लोजर का मतलब यह तय करना नहीं है कि आप शो में बने रहने के लायक थे या आप बेहतर कर सकते थे।

असली क्लोजर यह स्वीकार करना है कि कहानी उस तरह खत्म नहीं हुई, जिस तरह हमने अपने दिमाग में लिखी थी। बता दें कि खतरों के खिलाड़ी 15 में अविका गौर का सफर शो के दूसरे हफ्ते में ही खत्म हो गया था। एलिमिनेशन स्टंट में उनका मुकाबला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामानी यानी ओरी से हुआ था। ओरी ने यह स्टंट करीब 10 मिनट में पूरा कर लिया, जबकि अविका को इसे पूरा करने में 13 मिनट से ज्यादा का समय लगा। इसके बाद उनका शो का सफर खत्म हो गया।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website : aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com